● वर्ष-5

● अंक-160

रायपुर, बुधवार
18 फरवरी 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› जनजातीय समाज के ...

हिंदू धर्म में वापस लौटे लोगों का ध्यान रखना जरूरी...

मोहन भागवत ने घर वापसी पर दिया जोर

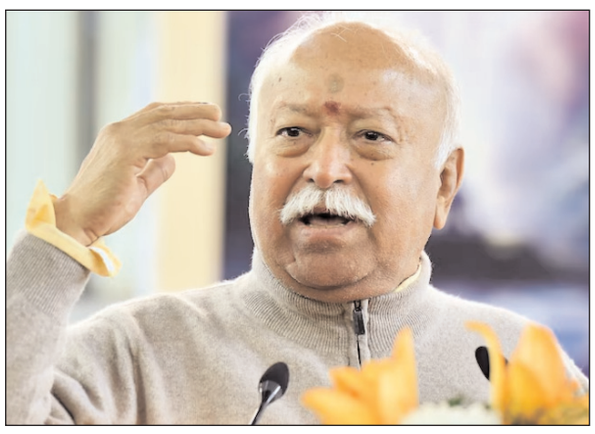

नईदिल्ली। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को लेकर सजग रहना जरूरी है। लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक में भागवत ने हिंदू समाज से संगठित और सशक्त बनने का आह्वान किया।

बैठक में उन्होंने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई और लालच या जबरन हो रहे मतांतरण पर रोक लगाने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि घर वापसी के प्रयासों को गति दी जानी चाहिए और जो लोग हिंदू धर्म में वापस आते हैं, उनके सामाजिक पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी भी समाज को उठानी होगी।

घुसपैठ के मुद्दे पर भी की बात

घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें हटाने की नीति अपनाई जानी चाहिए। उनके अनुसार, ऐसे तत्वों को रोजगार या अन्य सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। परिवार व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाज की स्थिरता के लिए संतुलित जनसंख्या आवश्यक है। वैज्ञानिकों के हवाले से उन्होंने दावा किया कि यदि किसी समाज में औसतन तीन से कम बच्चे होते हैं, तो वह समाज दीर्घकाल में कमजोर हो सकता है।

उन्होंने नवदंपतियों को परिवार के प्रति कर्तव्यबोध समझाने की जरूरत बताई और कहा कि विवाह का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि सृष्टि के संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ा है।सद्भाव के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि भेदभाव समाज को कमजोर करता है। हम सभी एक देश और एक मातृभूमि के पुत्र है। मनुष्य होने के नाते हम सब एक हैं,उन्होंने कहा- उनके अनुसार, सनातन विचारधारा का मूल भाव समन्वय और सद्भाव है, न कि विरोधियों को मिटाने की भावना। मातृशक्ति की भूमिका पर उन्होंने कहा कि परिवार का आधार महिला है। भारतीय परंपरा में महिलाओं को 'माता' के रूप में सम्मानित किया गया है। उन्होंने महिलाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर जोर दिया और कहा कि उन्हें अबला नहीं, बल्कि शक्तिस्वरूपा समझा जाना चाहिए।

सभी करें कानून का पालन-

कानून और सामाजिक मुद्दों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए, और यदि कोई कानून त्रुटिपूर्ण है तो उसे संवैधानिक तरीकों से बदला जा सकता है। जातीय भेदभाव पर उन्होंने कहा कि समाज में अपनेपन का भाव बढ़ेगा तो ऐसी समस्याएं स्वत: कम होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत भविष्य में विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखता है और अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान भारतीय चिंतन में निहित है।

बैठक में सिख, बौद्ध और जैन समाज के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने बस्ती स्तर पर नियमित सामाजिक सद्भाव बैठकों के आयोजन का आह्वान किया, ताकि संवाद के माध्यम से गलतफहमियों को दूर किया जा सके और समाज में समन्वय को मजबूत किया जा सके।

एआई समिट के बीच सुप्रीम चिंता वकील एआई से बना रहे याचिकाएं

नई दिल्ली। एक तरफ भारत दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन एआई इम्पैक्ट समिट-2026 की मेजबानी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एआई के गलत इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने कहा कि कुछ वकील याचिकाएं तैयार करने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ऐसी याचिकाएं दाखिल हो रही हैं जिनमें ऐसे फैसलों का हवाला दिया गया है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं हैं।

पीठ में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी इस पर चिंता जताई। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कई बार असली फैसलों का नाम दिया जाता है, लेकिन उनमें फर्जी उद्धरण जोड़ दिए जाते हैं, जिससे जांच करना मुश्किल हो जाता है और जजों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत में भी ऐसे कई मामलों का हवाला दिया गया था, जो असल में मौजूद नहीं थे। जस्टिस बागची ने कहा कि कानूनी ड्राफ्टिंग की कला में गिरावट आई है। कई याचिकाओं में सिर्फ पुराने फैसलों के लंबे-लंबे उद्धरण होते हैं, लेकिन अपने तर्क बहुत कम होते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस समय आई जब अदालत राजनीतिक भाषणों को लेकर दिशा-निर्देश मांगने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी में पांच दिवसीय एआई इम्पैक्ट समिट-2026 की शुरुआत सोमवार को हुई। भारत मंडपम में आयोजित इस सम्मेलन में टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रमुख, उद्योगपति, नीति-निर्माता और विशेषज्ञ बड़ी संख्या में शामिल हुए। सम्मेलन स्थल पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी गईं। शहर भर में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। भारत इस मंच के जरिए एआई तक व्यापक पहुंच और वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में अपनी पहल को आगे बढ़ा रहा है।

भारत और फ्रांस के बीच 20+ समझौते

मैक्रों ने बताईं दोनों देशों के संबंधों की तीन खास बातें

मुंबई। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी में हुए भारत-फ्रांस समिट के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में 20 से अधिक समझौतों की घोषणा की गई. इनमें डिफेंस, स्किलिंग, टेक्नोलॉजी और हेल्थ जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल है। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी. समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और पीएम मोदी ने कर्नाटक में ॥125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया. इस मौके पर भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री कर्नाटक में मौजूद रह।

यह एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स का जॉइंट वेंचर है. 'मेक इन इंडिया' इनिशिएटिव के तहत स्थापित की गई यह असेंबली लाइन भारत में डिफेंस और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि नई दिल्ली और पेरिस के बीच साझेदारी किसी सीमा में बंधी नहीं है और यह गहरे महासागरों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच रखती है.

उन्होंने कर्नाटक में एच125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन के उद्घाटन का जिक्र करते हुए कहा, हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला, विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और पूरे विश्व को एक्सपोर्ट करेंग। पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2026, भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है. हम इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ, इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्कीलिंग इन एयरोनॉटिक्स लॉन्च करने जा रहे है।

सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं भारत-फ्रांस संबंध

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच संबंध वास्तव में अनूठे है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के नेतृत्व में इस साझेदारी को अभूतपूर्व गहराई और नई गतिशीलता मिली है. उन्होंने कहा, आपसी विश्वास और साझा दृष्टि की मजबूत नींव पर खड़े ये संबंध अब स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक पहुंचाए जा रहे है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026

तकनीक और मानव का मेल तय करेगा एआई का भविष्य

दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दूसरे दिन भी देश-दुनिया के कई दिग्गज नेता और लीडर्स उपस्थित रहे। इस दौरान संस्कृति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार रंजना चोपड़ा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि यह समिट विभिन्न मंत्रालयों, स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों को अपने एआई नवाचार दिखाने का शानदार अवसर दे रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाल ही में एक डिजिटल समाधान विकसित किया है, जिसके जरिए कंटेंट को चार जनजातीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। इस पहल को

समिट में काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और कई एजेंसियों ने इसमें रुचि दिखाई है।उन्होंने आगे कहा कि यह समिट युवाओं के लिए भी बेहद उपयोगी है, क्योंकि यहां वे अपने रोजमर्रा की समस्याओं के लिए विकसित एआई समाधान देख सकते हैं। साथ ही यह मंच उन्हें प्रेरणा, नेटवर्किंग और रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। वहीं, सीओएआई (सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. एसपी कोचर ने टेलीकॉम सेक्टर में एआई की भूमिका पर बात करते हुए कहा कि एआई का पूरा संचालन टेलीकॉम नेटवर्क पर ही निर्भर करता है। डेटा सेंटर में डेटा स्टोर होता है, लेकिन उसे लाने-ले जाने का काम टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए ही होता है। उन्होंने कहा कि 5जी नेटवर्क पर अभी तक पूरी तरह से व्यावसायिक लाभ नहीं मिला है, लेकिन एआई एक ऐसी तकनीक है जिससे 5जी के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे।उन्होंने कहा कि समिट में दिखाई जा रही एआई एप्लिकेशन आम लोगों के लिए उपयोगी हैं और उनकी खपत बढ़ने से टेलीकॉम नेटवर्क को भी फायदा होगा। आने वाले समय में 5जी नेटवर्क पर एआई आधारित सेवाओं से नेटवर्क और अधिक सक्षम होगा। डॉ. कोचर ने जोर देकर कहा कि दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक मजबूत नेटवर्क पहुंचाना बेहद जरूरी है। बिना कनेक्टिविटी के एआई वहां काम नहीं कर सकता।

प्रमुख समाचार

एआई समिट में कुप्रबंधन से वैश्विक शर्मिंदगी: खरगे

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को एआई शिखर सम्मेलन के कथित कुप्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि भारत के लिए एक शानदार आयोजन बन सकने वाला यह कार्यक्रम पूरी तरह से अराजकता में तब्दील हो गया। खर्गे ने कहा कि भोजन और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण आगंतुकों और प्रदर्शकों दोनों को ही

अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। एक्स पर एक पोस्ट में, खरगे ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि शिखर सम्मेलन, जिससे भारत की डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की उम्मीद थी, कथित तौर पर बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन का शिकार हुआ। खरगे ने कहा कि भारत की डिजिटल और एआई क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला, पूरी दुनिया के लिए एक शानदार एआई शिखर सम्मेलन बन सकने वाला यह कार्यक्रम, कथित तौर पर इस पीआर के भूखे सरकार द्वारा पूरी तरह से अराजकता और घोर कुप्रबंधन में तब्दील हो गया है! कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे आरोप लगाया कि आयोजन के दौरान की गई।

भूपेन बोरा 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होंगे : हिमंत

गुवाहाटी । असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को घोषणा की कि पूर्व राज्य कांग्रेस प्रमुख भूपेन बोरा 22 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होंगे। यह घोषणा तब हुई जब सरमा मंगलवार शाम गुवाहाटी में बोरा से उनके घर पर मिले। रिपोर्टरों से बात करते हुए, सरमा ने कहा, भूपेन बोरा 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होंगे। दिलीप सैकिया डिटेल्स पर काम

करेंगे। उनके साथ, गुवाहाटी और उत्तरी लखीमपुर में कई कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल होंगे।

सीएम सरमा ने बोरा को कांग्रेस में आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू नेता बताया और कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले ही उनके शामिल होने को मंजूरी दे दी है। सरमा ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहले ही उनके शामिल होने को मंजूरी दे दी है और उनका स्वागत करते हैं। भूपेन बोरा को पूरा सम्मान और गरिमा दी जाएगी। इस कदम को घर वापसी बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा में शामिल होना उनके लिए घर वापसी जैसा होगा क्योंकि यह एक ऐसी पार्टी है जिसमें उनके जैसे कई लोग हैं, जिनके पिता किसी बड़े पद पर नहीं रहे।

डीयू में प्रदर्शन और नारेबाजी पर एक महीने तक पूरी तरह रोक

दिल्ली। विश्वविद्यालय(डीयू) परिसर में एक महीने के लिए किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा, जुलूस और प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार ने छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और स्टाफ को सूचित करने के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश को मंगलवार से ही लागू कर दिया गया है।प्रो. मनोज कुमार के अनुसार यह आदेश इस जानकारी

के आधार पर जारी किया गया है कि डीयू परिसर में बिना रोक-टोक के सार्वजनिक समारोहों, जुलूस या प्रदर्शन से ट्रैफिक में रुकावट, इंसानी जान को खतरा और जनशांति भंग हो सकती है। पहले भी आयोजक अक्सर ऐसे छात्र विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में असफल रहे हैं। जिससे विश्वविद्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है।प्रॉक्टर ने आदेश में सब डिविजन सिविल लाइंस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के 26 दिसंबर 2025 वाले आदेश का हवाला दिया है। जिसमें गृह मंत्रालय की अधिसूचना का विवरण दिया गया है। इसमें विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी सार्वजनिक सभा, रैली, धरने प्रदर्शन, आंदोलन और किसी भी ऐसी गतिविधि पर रोक के आदेश है।

पांच राज्यों के चुनाव की तारीख का एलान

नईदिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम मार्च के मध्य में घोषित कर सकता है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इन चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान अप्रैल में अलग-अलग

तारीखों पर होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग सभी पांच विधानसभाओं के चुनाव की तारीखें मार्च के मध्य में एक साथ घोषित करने की योजना बना रहा है। हालांकि, मतदान राज्य के अनुसार कई चरणों में भी हो सकता है। पांचों विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है, जबकि असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमश: 20 मई, 23 मई, 10 मई और 7 मई को समाप्त होगा। चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव वाले राज्यों का दौरा कर रहा है।

राजपाल यादव को सलाखों से मिली आजादी

नईदिल्ली। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव फाइनली तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. सलाखों के पीछे 12 दिन बिताने के बाद उनकी रिहाई हो गई है. बीते दिन यानी सोमवार को दिल्ली की हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. 17 फरवरी, मंगलवार को एक्टर जेल से रिहा हो गए हैं. 9 करोड़ कर्ज केज में लंबे समय

से चल रहे कानूनी विवाद के बाद ये राहत उन्हें मिली है. जेल से बाहर आने के बाद राजपाल मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने कहा कि कोई लीगल जानकारी हो तो वो आप हमारे वकील भास्कर से ले सकते हैं. बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बॉलीवुड में 30 साल हो जाएंगे. पूरे देश का बच्चा-बच्चा मेरे साथ रहा तभी तो मैं 250 फिल्में कर पाया. पूरा बॉलीवुड मेरे साथ खड़ा रहा. भारतीय सिनेमा का बच्चा बुढ़ा नौजवान मेरे कलेजे का टुकड़ा है. सब मेरे साथ था और साथ है। राजपाल ने आगे कहा- पिछले 10 सालों में माननीय हाई कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं, वो मैंने माना है. आगे भी जहां-जहां वो कहेंगे हाजिर होने को बिल्कुल मैं हाजिर होऊंगा।

विमर्श

भारत की एआई नीतियां अन्य देशों की तुलना में ज्यादा समावेशी

कमलेश पांडे

भारत की एआई लोकतंत्रीकरण नीतियां दुनिया के अन्य देशों यानी अमेरिका-चीन-यूरोप की तुलना में ज्यादा समावेशी, ओपन-सोर्स और ग्लोबल साउथ-केंद्रित हैं।भारत का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न और लोककल्याणकारी है। जहां अमेरिका और चीन एआई को प्रमुख कंपनियों के एकाधिकार के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, वहीं भारत सार्वजनिक संसाधनों (जैसे ऐरावत पर लामा मॉडल्स) को एपीआई के जरिए सस्ता उपलब्ध कराता है।

यही वजह है कि भारत बनाम अन्य देश की विशेषताओं के दृष्टिगत पारस्परिक होड़ जारी है, खासकर भारत, अमेरिका, चीन व यूरोप के बीच। क्योंकि भारत का फोकस किसान, छात्र, स्टार्टअप्स के लिए भाषिणी, किसान ई-मित्र जैसे क्षेत्रीय अनुप्रयोग हैं, जबकि अमेरिका, चीन व यूरोप में बड़े टेक दिग्गजों का वर्चस्व है जो सख्त जोखिम नियमन से परेशान दिखाई देते हैं।

यही वजह है कि नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रस्तावित एआई लोकतंत्रीकरण के लिए नीतिगत सिफारिशें मुख्य स्थान रखती हैं, क्योंकि ये सिफारिशें प्रमुख रूप से सार्वजनिक एआई संसाधनों को किफायती और सुलभ बनाने पर केंद्रित होंगी। ऐसा इसलिए कि ये सिफारिशें ग्लोबल साउथ के देशों के लिए ओपन-सोर्स मॉडल्स, कम लागत वाली कंप्यूटिंग और कौशल विकास को बढ़ावा देंगी।

एआई लोकतंत्रीकरण के लिए नीतिगत प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं- पहला, एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज वर्किंग ग्रुप (भारत, मिस्र, केन्या सह-अध्यक्ष) द्वारा एपीआई - आधारित सस्ते एआई मॉडल्स को उपलब्ध कराना, ताकि स्टार्टअप्स, किसान और छात्र लाभान्वित हों।

दूसरा, जोखिम-आधारित शासन- इंडिया एआई गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुरूप उच्च-जोखिम एआई के लिए सुरक्षा उपाय, मौजूदा कानूनों (आईटी अधिनियम, डीपीडीपी पर आधारित बिना नए नियामक निकाय।

तीसरा, समावेशी इकोसिस्टम- भाषिणी जैसे प्लेटफॉर्म्स से क्षेत्रीय भाषाओं में एआई कंटेंट, टियर-2/3 शहरों में नवाचार को प्रोत्साहन।

जहां तक इनके अपेक्षित प्रभाव की बात है तो ये सिफारिशें एआई एकाधिकार को तोड़कर भारत को ह्यूमन-सेंट्रिक एआई मॉडल के रूप में स्थापित करते हुए रोजगार सृजन और सतत विकास सुनिश्चित करेंगी। समिट के चक्रों से निकलने वाली ये प्रतिबद्धताएं वैश्विक मानक बनेंगी।

नीतियां कैसे भिन्न

भारत की एआई लोकतंत्रीकरण नीतियां अन्य देशों से मुख्य रूप से समावेशी, ओपन-सोर्स और ग्लोबल साउथ-केंद्रित दृष्टिकोण से भिन्न हैं। जहां अमेरिका और चीन एआई को प्रमुख कंपनियों के एकाधिकार के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, वहीं भारत सार्वजनिक संसाधनों को एआई के जरिए सस्ता उपलब्ध कराता है।

यही वजह है कि भारत बनाम अन्य देश की विशेषताओं के दृष्टिगत पारस्परिक होड़ जारी है, खासकर भारत, अमेरिका, चीन व यूरोप के बीच। क्योंकि भारत का फोकस किसान, छात्र, स्टार्टअप्स के लिए भाषिणी, किसान ई-मित्र जैसे क्षेत्रीय अनुप्रयोग हैं, जबकि अमेरिका, चीन व यूरोप में बड़े टेक दिग्गजों का वर्चस्व है जो सख्त जोखिम नियमन से परेशान दिखाई देते हैं।

वहीं शासन के अनुरूप भारत जोखिम-आधारित, मौजूदा कानूनों पर निर्भर है, वो भी बिना नए नियामक के, अमेरिका, यूरोप, चीन में बाजार-प्रेरित, न्यूनतम हस्तक्षेप होते रहने से कठोर अनुपालन और स्वतंत्र ऑडिट की राह में मुश्किल आती हैं।वहीं पहुंच के मद्देनजर भारत सरकारी क्लाउड (मेघराज), 10,000 करोड़ मिशन से किफायती कंप्यूटिंग लगेगी। जबकि अमेरिका, चीन, यूरोप में निजी क्लाउड, उच्च लागत होने से नियामक अनुपालन पर जोर दिया जाता है।

जहां तक प्रमुख भिन्नताएं की बात हैं तो भारत का मॉडल विविध भाषाओं (भाषिणी) और टियर-2/3 शहरों पर केंद्रित है, जो विकासशील देशों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है, जबकि पश्चिमी नीतियां गोपनीयता और सुरक्षा पर अधिक सख्त हैं। यह दृष्टिकोण एआई को सभी के लिए बनाता है, न कि चुनिदा लागों लिए। हालांकि एआई लोकतंत्रीकरण नीतियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, नैतिकता और संसाधनों से जुड़ी हैं। ये चुनौतियां भारत जैसे विकासशील देशों में अधिक गंभीर हैं।

महिला समेत 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा। छत्तीसगढ़ में मार्च महीने से पहले नक्सल विरोधी अभियान तेज हो गए हैं। बड़ी संख्या में नक्सली भी संगठन छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं।

सुकमा जिले में मंगलवार को जवानों को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली। 22 माओवादियों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसमें 21 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं।पुलिस अधिकारी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली जगरगुण्डा, पेद्दाबोडकेल और मोरपल्ली जैसे इलाके में सक्रिय है। इस सफलता में डीआरजी सुकमा, जिला बल सुकमा, रेंज फिल्ड टीम (आरएफटी) जगदलपुर और सीआरपीएफ 02, 74, 111, 223, 227 और कोबरा 201 वाहिनी के आसूचना शाखा की विशेष भूमिका रही है।

इन नक्सलियों ने चुनी संविधान की राह

गोंचे हुंगा पिता गोंचे आयता - ग्राम एलमपल्ली जीआरडी मिलिशिया कमांडर, निवासी एलम्मपल्ली (बेडमा) थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा। मड़कम बण्डी पिता धुरवा -पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा। माड़वी हांदा पिता स्व। माड़वी हिडमा -पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भिम्मापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा। मड़कम नन्दा पिता स्व। मल्ला - पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा।

मड़कम रामा पिता मड़कम बुधरा - पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी मड़कम सोमड़ा पिता स्व। मड़कम बया - पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा। मिडियाम आयता पिता स्व। मिडियाम हुर्रा -बेड़मा आरपीसी जंगल कमेटी अध्यक्ष, निवासी वेडमा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा। मड़कम चैतु पिता स्व। मड़कम सुक्का -बेड़मा आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी वेडमा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा। माड़वी हुंगा पिता बुधरा -पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी पेद्दाबोडकेल करकापारा थाना चिंतलनार जिला सुकमा।

लक्ष्मी मुचाकी पिता दूला -रेवाली/पोदेम पंचायत केएएमएस सदस्या, निवासी पोरदेम गोटगुड़ेम थाना गादीरास जिला सुकमा। गोंचे उर्फ मड़कम हुंगा पिता बण्डी उर्फ बुड़ता -पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी तिम्मापुरम पटेलपारा थाना चिंतलनार जिला सुकमा। माड़वी दूला पिता जोगा -पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी पेद्दाबोडकेल थाना चिंतलनार जिला सुकमा। कुंजाम केसा पिता स्व। मंगडू -बैयमपल्ली आरपीसी कृषि कमेटी अध्यक्ष, निवासी उरसांगल इत्तापारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा।

वेको विज्जा पिता भीमा उर्फ बक्का -गोण्डेरास पंचायत मिलिशिया सदस्य, निवासी नेण्डीपारा गोण्डेरास थाना फुलबगड़ी जिला सुकमा। वेको हड़मा पिता वेको जोगा -गोण्डेरास पंचायत मिलिशिया सदस्य, निवासी नेण्डीपारा गोण्डेरास थाना फुलबगड़ी जिला सुकमा। मुचाकी सुक्का पिता स्व। नंदा -गोगुण्डा पंचायत जनताना सरकार उपाध्यक्ष, निवासी गोगुण्डा उसकोनपारा थाना केरलापाल जिला सुकमा। माड़वी जोगा पिता स्व। भीमा -पेद्दाबोडकेल आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य, निवासी करकनगुड़ा सरपंचपारा थाना चिंतलनार जिला सुकमा। मड़कम पाण्डू पिता स्व। हुंगा - पेद्दाबोडकेल आरपीसी डीएकेएमएस उपाध्यक्ष, निवासी करकनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा। नुप्पो देवा पिता गगा -मोरपल्ली आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी कुमोड़तोंग पेरमापारा थाना पामेड़ जिला सुकमा। भोगाम दसरू उर्फ सोना पिता बोटी -बैयमपल्ली आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी उरसांगल बक्कापारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा। सलवम लखमा पिता भीमा - जोनागुड़ा आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी जोन्नागुड़ा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा।

जगत उर्फ मुचाकी भीमा पिता जोगा -बेड़मा आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य, निवासी दुरमा नयापारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा।

आत्मसमर्पित माओवादियों को मिलेगा पुनर्वास नीति का लाभ

आत्मसमर्पित माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगी। मुख्यधारा में लौटने पर हर नक्सली को 50-50 हजार रुपये के मान से प्रोत्साहन राशि दी गई। इन्हें आगे अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।

विश्व प्रसिद्ध फागुन मेला में पहुंचेगे विदेशी पर्यटक

- दंतेवाड़ा में विश्व प्रसिद्ध फागुन मेला की तैयारियां पूरी हो चुकी है.इस बार जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी ने मिलकर विशेष प्लान बनाया है.

दंतेवाड़ा। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध फागुन मेला की तैयारी पूरी हो चुकी है।विश्व प्रसिद्ध फागुन मेला हर साल बस्तर की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का अनूठा संगम पेश करता है। इस बार फागुन मेला पहले से भी ज्यादा भव्य और व्यवस्थित करने की तैयारी है। मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने मिलकर 2026 के फागुन मेला के लिए व्यापक तैयारी की है। लगातार बैठकों और समीक्षा के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, ताकि मेले में दूर-दूर से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। साल 2025 में आई प्राकृतिक आपदा के कारण दंतेवाड़ा को जोड़ने वाला बाईपास पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद से भारी वाहनों का आवागमन दंतेश्वरी मंदिर मार्ग से होने लगा।इस बदली व्यवस्था के कारण भीड़ के साथ यातायात की चुनौतियां बढ़ गई। इसी पृष्ठभूमि में प्रशासन और मंदिर कमेटी ने इस साल फागुन मेला सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की है। मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने तय किया है कि फागुम मेला की संभी पारंपरिक रस्में उसी जगह पर होगी जहां पहले से होती आ रही है। बस्तर की विरासत से जुड़ी ये रस्में मेले की आत्मा हैं, जिन्हें उनके मूल रूप में ही पूरा कराया जाएगा। नौ दिनों तक चलने वाले इन आयोजनों में स्थानीय परंपराओं, देव-धर्म और बस्तरिया संस्कृति का दिव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। इस बार बाहर से आने वाले व्यापारियों के लिए प्रशासन ने 10म10 फीट का चिह्नित स्थान आवंटित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक दुकान के लिए बिजली व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि व्यापारी निर्बाध रूप से अपना कारोबार कर सकें।मेले में बड़ी संख्या में व्यापारी आते हैं, इसलिए सुव्यवस्थित दुकान क्षेत्र मेले के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेले में भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने इस साल एक बड़ा बदलाव किया है। आकाश झूला, सर्कस, प्रदर्शनी तथा बच्चों के झूले को दंतेश्वरी मंदिर परिसर से दूर दंतेवाड़ा ऑडिटोरियम के पीछे ट्रांसफर किया गया है। इससे मंदिर क्षेत्र का दबाव कम होगा और लोग बिना अवरोध पूजा-अर्चना और रस्मों में शामिल हो सकेंगे। पार्किंग व्यवस्था और भी सुदृढ़भीड़ को डायवर्ट करने और वाहन व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने पार्किंग के लिए दंतेवाड़ा हाईस्कूल को चिह्नित किया है। यहां वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।नई जगह व्यवस्थित पार्किंग होने के कारण जाम की समस्या से भी काफी हद तक राहत मिलेगी। पार्किंग से लेकर दुकान क्षेत्र तक आने-जाने के लिए अलग-अलग मार्ग तय किए गए हैं।यातायात पुलिस की विशेष योजनायातायात पुलिस ने मेले के लिए एक विस्तृत नक्शा तैयार किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि इस बार मेला किन क्षेत्रों में लगेगा, दुकानें किस स्थान पर होंगी और पार्किंग कहां होगी। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोग और पर्यटक किसी भी प्रकार की उलझन में न पड़ें। मेले को शांतिपूर्ण एवं गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल, यातायात विभाग, नगर पालिका, टेंपल कमेटी और सर्व समाज के लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सुरक्षा, सफाई, व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं के लिए टीमें गठित की गई हैं।मंदिर के प्रधान पुजारी जिया महाराज ने आम जनता से अपील की है कि वे स्थिति को समझते हुए प्रशासन का सहयोग करें।

पूर्व सेवा को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज, पीजीटी/टीजीटी अतिथि शिक्षकों को सेवा में लेने का दिया आदेश

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों के लिए नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा जारी केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया में यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि लंबे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की पूर्व सेवाओं को नियुक्ति प्रक्रिया में समुचित महत्व दिया जाए तथा उनके अनुभव के लिए यथोचित अंक प्रदान कर उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए। इस प्रकरण में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने पक्ष प्रस्तुत किया।

याचिकाकर्ता वर्ष 2016 से 2024 के मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में स्थित ईएमआरएस विद्यालयों में पीजीटी एवं टीजीटी के रूप में कार्यरत रहे हैं। इन सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एके प्रसाद ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्वीकार किया कि अनेक याचिकाकर्ताओं ने छह वर्ष से अधिक अवधि तक दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों में निष्ठापूर्वक शिक्षण कार्य किया है, और विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यद्यपि अस्थायी अथवा अतिथि सेवा के आधार पर नियमितीकरण का कोई स्वचालित या वैधानिक अधिकार उत्पन्न नहीं होता, तथापि न्याय, समानता और प्रशासनिक निष्पक्षता की दृष्टि से उनकी दीर्घकालीन सेवा को नज़रअंदाज़ करना उचित नहीं होगा। इसी संदर्भ में न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि ह्श्वस्ञ्जस् तथा राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ताओं की पूर्व सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनुभव के आधार पर उपयुक्त अंक/वेटेज प्रदान करें तथा पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर उनकी नियुक्ति पर विचार करें। न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि वर्षों तक की गई सेवा को व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता और उसका प्रभावी मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश स्वत: नियमितीकरण या प्रत्यक्ष नियुक्ति का निर्देश नहीं है।

बलौदाबाजार जिले में फिर गरमाया अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा

बलौदाबाजार। जिले में अवैध रेत खनन को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। लवन थाना प्रभारी रहे निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह का तबादला आदेश जारी होते ही प्रशासनिक हलकों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। यह तबादला ऐसे समय हुआ है, जब बताया जा रहा है कि उन्होंने अवैध और ओवरलोड रेत परिवहन के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की थी। कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा 16 फरवरी 2026 को जारी आदेश क्रमांक /स्थापना/ 1026/2026 के तहत तीन निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। आदेश में इसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिया गया निर्णय बताया गया है। हालांकि, जिस समय यह आदेश जारी हुआ और जिस संदर्भ में इसे देखा जा रहा है, उसने पूरे मामले को संवेदनशील बना दिया है। जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक शशांक सिंह ठाकुर को सुहेला से हटाकर प्रभारी थाना लवन पदस्थ किया गया है। निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह को लवन से प्रभारी थाना राजदेवरी भेजा गया है। वहीं निरीक्षक धीरेंद्र नाथ दुबे को राजदेवरी से प्रभारी थाना सुहेला पदस्थ किया गया है।सामान्य प्रशासनिक फेरबदल के रूप में देखे जाने वाले इस आदेश ने अचानक इसलिए ध्यान खींचा क्योंकि इसके ठीक पहले लवन क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सामने आई थीं। जानकारी के अनुसार निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने हाल ही में ओवरलोड रेत परिवहन कर रही हाइवा और ट्रैक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया था।बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई महानदी क्षेत्र से अवैध उत्खनन कर लाई जा रही रेत पर की गई थी। हालांकि पुलिस विभाग की ओर से इस कार्रवाई का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। यही वह बिंदु है, जिसने तबादले को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि यदि कार्रवाई प्रभावी थी और अवैध खनन के खिलाफ सख्ती दिखाई जा रही थी, तो अचानक तबादले की जरूरत क्यों पड़ी।

बलौदाबाजार जिला लंबे समय से महानदी से हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर सुर्खियों में रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन और परिवहन होता है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सूखे नशे के कारोबार में महिलाएं भी सक्रिय हुए

बिलासपुर। बिलासपुर जिले में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में अलग-अलग थाना क्षेत्रों से गांजा और नशीली टेबलेट के अवैध कारोबार में संलिप्त 4 महिलाओं समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 8 किलो से अधिक गांजा और 2925 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट जब्त की गई। यह कार्रवाइयां सरकंडा, सिविल लाइन, बेलगहना, सीपत, कोनी, कोटा, रतनपुर, बिल्हा और सिरगिट्टी थाना क्षेत्रों में की गई है। पुलिस ने 12 गांजा तस्कर और 1 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट विक्रेता दबोचे गए हैं। जब्त 2925 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट की कीमत 11,497 रुपए आंकी गई है। कोनी पुलिस ने अवैध गांजा बिक्री मामले में आरोपी महिला पूर्णिमा वर्मा को गिरफ्तार किया है। महिला के कब्जे से 1 किलो 256 ग्राम गांजा और मोबाइल बरमाद किया है। जप्त मशरूका की कुल कीमत 36,000 रुपए आंकी गई। आरोपिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बीजेतला और पटेवा में खुलेगा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

राजनांदगांव। जिले के पटेवा ग्राम में करीब 350 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी -2.0 और ग्राम बिजेतला में 25 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के पहले स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा किसानों से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। अब तक बीजेभांठा और पटेवा में ढाई सौ एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित किए जाने के बाद प्रक्रिया तेज हो गई है। उद्योग विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार 375 करोड़ की लागत से ईएमसी और एसएमसी की स्थापना की जानी है। विगत दिनों विधानसभा अध्यक्ष डां रमन सिंह ने राज्य शासन की स्वीकृति दिए जाने की जानकारी दी थी। जिसके बाद उद्योग विभाग द्वारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। पटेवा के आलावा ग्राम बिजेतला में 25 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के पहले स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना होगी। इन परियोजनाओं से रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

जटकन्हार पोस्ट ऑफिस घोटाले पर चक्काजाम आंदोलन

डोंगरगढ़। जटकन्हार पोस्ट ऑफिस में करोड़ों रुपये के कथित फर्जीवाड़े से आक्रोशित ग्रामीण खाताधारकों ने सोमवार को डोंगरगढ़ स्थित पोस्ट ऑफिस पहुंचकर अपनी जमा राशि वापस करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। जिम्मेदार अधिकारियों के अनुपस्थित रहने से नाराज ग्रामीणों ने पोस्ट ऑफिस के सामने रेलवे स्टेशन रोड जाम कर धरना दे दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। शहर का मुख्य मार्ग शाम तक अवरुद्ध होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि पोस्ट मास्टर और फील्ड ऑफिसर दोनों अवकाश पर चले गए हैं। दफ्तर में केवल पोस्टमैन मौजूद थे, जिन्होंने प्रभारी फील्ड ऑफिसर के खैरागढ़ से आने की बात कहकर चुप्पी साध ली। अधिकारियों की गैर मौजूदगी से आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर आए और रेलवे स्टेशन रोड पर बैठकर धरना देने लगे। अचानक हुए रोड ब्लॉक की सूचना पुलिस को तत्काल नहीं मिल सकी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

खमरिया-सोंठी-नवापारा मार्ग के उन्नयन की प्रक्रिया तेज

बिलासपुर। जिला बिलासपुर के बहुप्रतीक्षित खमरिया-सोंठी-नवापारा मार्ग (लंबाई 12.00 कि.मी.) के उन्नयन कार्य को लेकर सकारात्मक प्रगति हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल 25.37 करोड़ के इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, नया रायपुर को प्रेषित कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के ईई सीएस विंध्यराज ने बताया कि मंत्रालय स्तर पर आवश्यक तकनीकी सुधार एवं औपचारिकताओं की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में उप अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी को मंत्रालय स्तर पर बुला कर आवश्यक संशोधन कराए गए, जिसके बाद प्रकरण अब प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस मार्ग के निर्माण/उन्नयन से क्षेत्र के ग्रामीणों, किसानों एवं दैनिक आवागमन करने वाले नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। सड़क की स्थिति बेहतर होने से परिवहन सुगम होगा, कृषि उपज के परिवहन में सुविधा मिलेगी।

ड्यूटी में शहीद जवान के परिवार को मिला सहारा

सुकमा। जिला पुलिस सुकमा द्वारा पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत दिवंगत डीएसएफ आरक्षक क्रमांक 2113 रामेश्वर नेगी के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की बीमा राशि दी गई। 10 मई 2025 की रात लगभग 9 बजे, रक्षित केंद्र सुकमा में पदस्थ डीएसएफ आरक्षक रामेश्वर नेगी पुलिस लाइन सुकमा से अपने गृह निवास छिंदगढ़ के लिए स्कूटी से रवाना हुए थे। रोज की तरह वह ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक पिकअप वाहन ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद परिजनों और साथियों द्वारा उन्हें जिला अस्पताल सुकमा में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने हरसंभव प्रयास किए, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसी रात लगभग 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। महज दो घंटे के भीतर एक परिवार का सहारा छिन गया। खबर मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। रामेश्वर नेगी एक समर्पित और अनुशासित पुलिसकर्मी के रूप में जाने जाते थे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्य किया।

दो महिला सटोरियों को किया गिरफ्तार

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में अवैध सट्टा गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो महिला सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई की गई, जिसमें नगद राशि और सट्टा-सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने कवर्धा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 01 शिवाजी कॉलोनी में मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। यहां नन्दिनीन उर्फ़ नीलू गुप्ता को खुद के घर के सामने अंकों पर सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं मौके से सट्टा-पट्टी, नगद रकम और पेन बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी कार्रवा वार्ड क्रमांक 05 लोहाराना देवारपारा क्षेत्र में की गई।

यहां पूजा बांधेकर अलग प्रकरण में सट्टा गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके विरुद्ध पृथक अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों महिला आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से अलग-अलग खाईवाली के नाम से सट्टा संचालन कर रही थी। उनके माध्यम से सट्टा खेलने और खिलाने वाले अन्य व्यक्तियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही अन्य संलिप्त लोगों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

10 करोड़ की लागत से बन रहे गौरव पथ में लापरवाही का आरोप

महासमुंद। जिला मुख्यालय में बनाये जा रहे गौरव पथ निर्माण में गंभीर लापरवाही बरते जाने का आरोप है। करीब 10 करोड़ की लागत से 2.3 किलोमीटर तक बनाए जा रहे इस गौरव पथ निर्माण का जिम्मा पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क निर्माण कंपनी किरण बिल्डकॉन बेमेतरा को दिया है। मई 2025 से शुरू हुआ यह निर्माण फरवरी तक पूरा होना था लेकिन लापरवाही पूर्वक किए जा रहे निर्माण के चलते अब तक केवल एक तिहाई ही काम पूरा हो पाया है। जिसके चलते स्थानीय निवासी काफी परेशान है ही, निर्माण की गुणवत्ता पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।

आरोप है कि सड़क के दोनों तरफ बनाये जा रहे नालियों, पेड़ों की कटाई और पोल शिफ्टिंग के दौरान, सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा लापरवाहीपूर्वक और मापदंड से हटकर गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है। इस दौरान दर्जनों बार पालिका द्वारा बिछाए गए मुख्य पानी सप्लाई पाइपलाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है, जिससे सैकड़ों लीटर पानी तो बर्बाद हो ही रहा है, स्थानीय निवासियों को कभी 02 तो कभी 4-4 दिनों तक पानी आपूर्ति की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जिससे वार्डवासी परेशान है। पालिका का भी दावा है कि पोल शिफ्टिंग और पेड़ शिफ्टिंग के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन निचले स्तर पर जहां मैन्युअल काम होना चाहिए वहां भी मशीन से काम होने के कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की समस्या सामने आ रही है।

लगातार बरती जा रही लापरवाही की शिकायत कलेक्टर महासमुंद से पहले भी हो चुकी है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को कार्य सही तरीके से करने से निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके सामने आ रही लापरवाही को लेकर अब कलेक्टर विनय कुमार लंगेह भी सख्त दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने गौरव पथ निर्माण की गुणवत्ता को जांचने के लिए थर्ड पार्टी टीम द्वारा जांच कमेटी बनाकर सड़क निर्माण की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दे दिए हैं। जिसमें अन्य विभाग के इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहेंगे।

संक्षिप्त समाचार

सुदूर अंचलों के श्रद्धालुओं को मिला अयोध्या धाम का सौभाग्य

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने

कोरिया प्रवास के दौरान झुमका जलाशय परिसर में 'श्री रामलला दर्शन योजना' के तहत अयोध्या धाम की पावन यात्रा कर लौटे श्रद्धालुओं से आत्मीय भेंट की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं का हाल-चाल जाना और उनके आध्यात्मिक एवं भक्तिमय अनुभवों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से उन्हें नि:शुल्क अयोध्या धाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सम्मानपूर्वक यात्रा की समुचित व्यवस्था किए जाने से यह यात्रा उनके लिए अत्यंत सहज और अविस्मरणीय बन गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि अपने सुदूर गांवों से अयोध्या तक पहुँचना उनके लिए पहले कठिन था, किंतु सरकार की पहल ने इसे संभव कर दिया। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री श्री साय को 'हमारे राम' तैलचित्र भेंट कर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम छत्तीसगढ़ के भांचा हैं और प्रदेशवासियों को उनके दर्शन कराना शासन के लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि सुदूर अंचलों में रहने वाले लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही जनसेवा की वास्तविक संतुष्टि है, और सरकार इसी भावना के साथ कार्य कर रही है।

मंत्री नेताम 20 फरवरी को करेंगे एकलव्य विद्यालयों की समीक्षा

रायपुर। आदिम जाति विकास मंत्री श्री

रामविचार नेताम की अध्यक्षता में 20 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान सेक्टर-24 अटल नगर, नवा रायपुर के सभाकक्ष में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस आशय का पत्र आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदेश के सभी सहायक आयुक्तों, प्राचार्यों और प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा भवन निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि को जारी कर दिया गया है। बैठक में निर्धारित समय एवं स्थान में एकलव्य विद्यालयों की अद्यतन स्थिति की जानकारी सहित अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

लेप्रोस्कॉपिक सर्जन की पदस्थापना से बलौदाबाजार जिला अस्पताल की बढ़ी क्षमता

रायपुर। जिला अस्पताल बलौदा बाज़ार में नए जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ क़ादिर बेग की पदस्थापना से अस्पताल की क्षमताओं में इज़ाफ़ा हुआ है। अस्पताल में अब हर्निया, हाइड्रोसिल,बवासीर,फिमोसिस,सेलुलाइटिसब्रेस्ट एबिस,फाइब्रोडेमा,लिम्फोमा,सिबेशियस सिस्ट जैसी गंभीर बीमारियों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश अवस्थी के अनुसार उक्त ऑपरेशन नि:शुल्क किये जा रहे हैं साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आयुष्मान कार्ड का भी उपयोग किया जाता है। भर्ती मरीज को भोजन नाश्ता भी दिया जाता है। सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि,उक्त ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थित अनुसार कुछ दिन भर्ती किया जाता है बाद में छुट्टी हो जाती है। सर्जन की पदस्थापना से अब तक 16 ऐसे ऑपरेशन किये जा चुके हैं। सेलुलाइटिस का उपचार करा चुके भाटापारा निवासी 45 वर्षीय अनिता के परिजनों ने बताया कि,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल रिफर किया गया था।उसके बाद वहां ऑपरेशन किया गया।इसमें आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला। एक हफ्ते भर्ती रहे उसके बाद छुट्टी हो गई। अभी स्थिति ठीक हैं।

मानिकपुर और अमेरी जलाशय के कार्यों के लिए 6.40 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़-शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के विकासखण्ड बरमकेला के अंतर्गत दो सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 6 करोड़ 40 लाख 27 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। स्वीकृत कार्यों में अमेरी जलाशय के जीर्णोद्धार तथा पिचींग एवं नहरों के सीसी लाईनिंग कार्य के लिए 3 करोड़ 25 लाख 90 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण हो जाने पर योजना का रूपाकिंत सिंचाई क्षेत्र 91 हेक्टेयर में 72 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा 46 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 137 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हो जाएगी। विकासखण्ड बरमकेला में मानिकपुर जलाशय के जीर्णोद्धार एवं नहर सीसी लाईनिंग कार्य के लिए 3 करोड़ 14 लाख 37 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने पर योजना का रूपांकित सिंचाई क्षेत्र 55 हेक्टेयर में 41 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा 52 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 107 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। सिंचाई योजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

उच्च शिक्षण संस्थानों को उभरते अवसरों के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा: टंक राम

'शिक्षा संवाद 2026' का भव्य शुभारंभ—उच्च शिक्षा, कौशल और रोजगार को जोड़कर विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा तय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा और कौशल विकास के भविष्य पर केंद्रित फ्लैगशिप कार्यक्रम 'शिक्षा संवाद 2026' का आज रायपुर के कोर्टयार्ड मैरियट में भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने किया। इस आयोजन का संचालन उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया, जिसमें एलिट्स टेक्नोमीडिया सहयोगी संस्था के रूप में जुड़ा रहा।

'विकसित छत्तीसगढ़ के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार का सेतु' थीम पर आधारित उद्घाटन सत्र में उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने, उद्योग की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों के समायोजन और क्षेत्रीय विकास प्राथमिकताओं पर विशेष चर्चा हुई।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा राज्य की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि

उच्च शिक्षण संस्थानों को उभरते अवसरों के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा। मंत्री ने संस्थागत क्षमता सुदृढ़ करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और पाठ्यक्रमों को उद्योग की मांग के अनुरूप ढालने पर बल दिया। साथ ही विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और उद्योग जगत के बीच संरचित समन्वय की आवश्यकता बताई, ताकि विद्यार्थियों को व्यावहारिक दक्षता और रोजगारपरक कौशल प्राप्त हो सके। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और नीतिगत सुधारों को भी गुणवत्ता सुधार का अहम माध्यम बताया गया।

कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने शासन के शिक्षा सुधारों, संस्थागत सशक्तीकरण और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि नीति के समुचित कार्यान्वयन, डिजिटल एकीकरण और परिणाम आधारित दृष्टिकोण से राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

इस अवसर पर एलिट्स टेक्नोमीडिया के सीईओ एवं एडिटर-इन-चीफ डॉ. रवि गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत करते हुए नीति, अकादमिक और उद्योग जगत के बीच सतत संवाद मंच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वहीं, उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने आगे बढ़कर ठोस कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया, जिससे शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास का समेकित मॉडल विकसित हो सके।

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और 'स्वयं प्लस ङ्क आईआईटी मद्रास' के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर रहा। इस समझौते के तहत उच्च गुणवत्ता वाले ऑनलाइन और ब्लेंडेड कोर्स, उद्योग-प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा क्रेडिट-लिंक्ड कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। इससे राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' के अंतर्गत क्रेडिट ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा तथा विद्यार्थियों को उन्नत कौशल आधारित मॉड्यूल्स का लाभ मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा विभाग ने मलेशिया के लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ भी एमओयू किया। इस सहयोग का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक साझेदारी, छात्र एवं संकाय विनिमय, संयुक्त शोध पहल और वैश्विक एक्सपोजर को बढ़ावा देना है।

शिक्षा संवाद 2026 में दिनभर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल नवाचार, उद्योग-अकादमिक सहयोग, शोध और उद्यमिता जैसे विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा संवाद 2026' ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच मजबूत सेतु बनाकर ही विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य साकार किया जा सकता है।

पर्यटन स्थलों के विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

■ मुख्यमंत्री ने झुमका जलाशय में बोटिंग और वाटर स्पोर्ट सुविधाओं का किया अवलोकन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कोरिया प्रवास के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बैकुंठपुर स्थित प्रसिद्ध झुमका पर्यटन स्थल में निर्मित ओपन थिएटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने झुमका जलाशय में बोटिंग करते हुए क्षेत्र के मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया तथा यहां विकसित की गई पर्यटन सुविधाओं का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने झुमका जलाशय में शिकारा पर सवार होकर नौका विहार किया। चारों ओर हरियाली, शांत जलराशि और कमल के फूलों से सजा यह रमणीय स्थल अब एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने यहां

बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स सहित विकसित पर्यटन गतिविधियों की जानकारी ली और व्यवस्थाओं की सराहना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने लगभग 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित ओपन थिएटर का लोकार्पण किया।500 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला यह ओपन थिएटर सांस्कृतिक आयोजनों के लिए नया केंद्र बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि झुमका जलाशय केवल कोरिया जिले की पहचान ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन स्थलों के विकास, सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में स्थापित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्यटकों की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए तथा स्थानीय युवाओं को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ।

इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक श्री भैयालाल राजवाड़े, संभागायुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा, आईजी श्री दीपक झा, कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक श्री रवि कुमार कुर्रे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

श्रम विभाग द्वारा घर पहुंच दिलाया जा रहा योजना का लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों के बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी क्रम में श्रम विभाग के अधीन संचालित छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना तहत पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी, नामिनी को योजनांतर्गत देय हितलाभ एक लाख रुपये का लाभ दिया जा रहा है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में विभाग द्वारा एक सतत अभियान चलाकर इस योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवारों के घर पहुच जाँच कर उनको लाभ दिलाया जा रहा है। निर्माण श्रमिक, असंगठित कर्मकार एवं उनके परिवार को दु:ख की घड़ी में आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है।

अम्बागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम सोनसायटोला के पंजीकृत श्रमिक स्व. श्री शम्भू राम के मृत्यु उपरांत यह राशि उनके उत्तराधिकारी फिरंतिन बाई को उनके खाते में हस्तांतरित की गयी। योजना अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर 1 लाख रूपए, कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रूपए कार्यस्थल पर दुर्घटना से स्थायी दिव्यंगता होने पर 2 लाख 50 हजार रूपए एवं अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1 लाख रूपए की अनुदान राशि प्रदान किया जाता है। योजना अंतर्गत निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार न्यूनतम 90 दिवस पूर्व का पंजीयन होना अनिवार्य है। आवेदन के

स्वीकृति उपरांत योजना की राशि डी.बी.टी के माध्यम से नामिनी, वैध उत्तराधिकारी के खाते में स्थानांतरित की जाती है। इस योजना का लाभ लेने हेतु योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक, पंजीकृत श्रमिक एवं नामिनी का आधार कार्ड एवं पूर्ण स्थायी पता के संबंध में प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा स्थायी दिव्यांगता होने पर डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि मंडल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री साय ने कुम्हार के चाक पर गढ़ा दीया

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का एक आत्मीय और सहज रूप उस समय देखने को मिला, जब उन्होंने कुम्हार के चाक पर स्वयं मिट्टी का दीया और कलश गढ़कर पारंपरिक शिल्प के प्रति सम्मान और जुड़ाव का सशक्त संदेश दिया। अवसर था सरगुजा विकास प्राधिकरण की

बैठक का, जिसमें शामिल होने वे कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर पहुंचे थे। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक के साथ परिसर में स्व-सहायता समूहों एवं स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इसी प्रदर्शनी में सोनहत विकासखंड निवासी शिल्पकार श्री देवी दयाल प्रजापति इलेक्ट्रिक चाक पर मिट्टी से दीया और कलश बनाने का सजीव प्रदर्शन कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय उनके स्टॉल पर पहुंचे और कुछ देर तक उनकी शिल्पकला का बारीकी से अवलोकन किया। कला के प्रति उत्सुकता बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने स्वयं चाक पर हाथ आजमाने की इच्छा व्यक्त की। शिल्पकार की सहमति से उन्होंने घूमते हुए चाक पर रखी गीली मिट्टी को हाथों से साधा और देखते ही देखते उसे सुंदर दीये का आकार दे दिया। मुख्यमंत्री की सहज कुशलता देखकर स्वयं शिल्पकार भी आश्चर्यचकित रह गए, वहीं उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गडग़ड़ाहट के साथ इस क्षण का स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान शिल्पकार देवी दयाल प्रजापति से उनके व्यवसाय, आय और परिवार की जानकारी ली तथा उन्हें शासन की विभिन्न स्वरोजगार एवं कारीगर हितैषी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारंपरिक शिल्प, कारीगरों और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि स्थानीय कला और हुनर को नई पहचान और बाजार मिल सके।

केन्द्रीय पर्यवेक्षकों ने छत्तीसगढ़ में पशुधन योजनाओं का लिया फीडबैक

दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले पहुंचकर योजनाओं का किया निरीक्षण

रायपुर। भारत सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय पर्यवेक्षकों का दल 09 से 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहा। इस दौरान वे पशुधन विकास विभाग के केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की छत्तीसगढ़ प्रगति की जानकारी ली केंद्रीय पर्यवेक्षकों को दल दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले का दौरा कर योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया और पशुपालकों से चर्चा की। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के दल ने छत्तीसगढ़ में पशुधन विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की सराहना की।

केंद्रीय दल प्रवास के प्रथम चरण में संचालनालय स्तर पर आयोजित ब्रीफिंग सत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव तथा भारत सरकार के नोडल अधिकारियों द्वारा योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। इसके पश्चात दल ने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर प्रशिक्षण गतिविधियों, प्रयोगशालाओं एवं पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों का अवलोकन किया। बालोद जिले के गुण्डरदेही एवं डौंडी विकासखंड में बिहान योजना से जुड़ी पशु सखियों से कार्यप्रणाली की जानकारी ली गई।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित बकरी पालन इकाइयों, हैचरी यूनिटों तथा दुग्ध संकलन केंद्रों का निरीक्षण कर पशुपालकों से संवाद किया गया। दुर्ग स्थित दुग्ध संघ संयंत्र में दुग्ध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग व्यवस्थाओं की

समीक्षा की गई। साथ ही पशु चिकित्सालयों एवं मोबाइल वेटेरिनरी इकाइयों में उपलब्ध दवाइयों व उपकरणों की जांच कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रवास के दौरान बालोद जिले में आयोजित जिला स्तरीय पशु मेले में भी दल ने सहभागिता की।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत टीम ने पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग का भ्रमण किया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही मैत्री एवं एवीएफओ रिफ्रेशर ट्रेनिंग संस्थान तथा शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित ई.टी.टी.-आई.वी.एफ. प्रयोगशाला का निरीक्षण किया गया। जिला बालोद के विकासखंड गुण्डरदेही एवं डौंडी में बिहान अंतर्गत कार्यरत 35 पशु सखियों से संवाद कर उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली गई।

नेशनल लाइवस्टॉक मिशन अंतर्गत ग्राम भरदा (दुर्ग) में श्री देवनाथ देशमुख, नवागांव (बेमेतरा) में श्रीमती मनीषा राजपूत तथा बालोद जिले के ग्राम गब्दी एवं बरही में संचालित बकरी इकाइयों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली गई। इसके अलावा बेमेतरा जिले के ग्राम खर्रा एवं सुरहोली स्थित स्काईलार्क हैचरी तथा बालोद जिले की एबीस हैचरी यूनिट का भी निरीक्षण किया गया।

नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट अंतर्गत टीम ने उरला (दुर्ग) स्थित छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ प्लांट का भ्रमण कर दुग्ध प्रसंस्करण, पैकेजिंग, घी एवं मक्खन निर्माण इकाई का अवलोकन कर जानकारी ली। बालोद जिले के अर्जुंदा तथा बेमेतरा जिले के सरदा एवं मौली भाठा स्थित दुग्ध संकलन केंद्रों का निरीक्षण कर पशुपालकों से चर्चा की गई।

इसी तरह लाइवस्टॉक हेल्थ एवं डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत बेमेतरा जिले में कोल्ड केबिनेट एवं शीत श्रृंखला उपकरणों का निरीक्षण किया। पशु चिकित्सालयों एवं मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट में उपलब्ध दवाईयों, टीकाकरण सामग्री एवं उपकरणों की जांच कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। ग्राम बोहारडीह (बेमेतरा) के उन्नत पशुपालक श्री मानसिंह वर्मा के डेयरी फार्म का भी अवलोकन किया गया। दौरे के दौरान जिला बालोद के ग्राम भेंगारी में आयोजित जिला स्तरीय पशु मेला में केन्द्रीय पर्यवेक्षकों की टीम शामिल हुई।

कोरबा में 18 फरवरी को होगा श्रमिक सम्मेलन का आयोजन

रायपुर। श्रम विभाग कोरबा द्वारा जिले के श्रमिकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से 18 फरवरी (बुधवार) को प्रात: 11 बजे से राजीव गांधी ऑडिटोरियम, टी.पी. नगर कोरबा में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित श्रमिक हितैषी योजनाओं की जानकारी एवं सुविधाएँ अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुँचाने हेतु आयोजित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री लखन लाल देवांगन, मंत्री - वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी) एवं श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद, कोरबा लोकसभा, श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत द्वारा की जाएगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर, नगर पालिक निगम कोरबा, श्रीमती संजू देवी राजपूत, अध्यक्ष, जिला पंचायत कोरबा, डॉ. पवन कुमार सिंह तथा सभापति, नगर पालिक निगम कोरबा, श्री नूतन सिंह ठाकुर सम्मिलित होंगे। सम्मेलन के दौरान श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदान करेंगे। श्रमिकों की सुविधा हेतु कार्यक्रम स्थल पर पंजीयन एवं नवीनीकरण काउंटर सहित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिससे श्रमिक भाई,बहन स्थल पर ही अपनी आवश्यक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सहायक श्रम आयुक्त कोरबा ने जिले के श्रमिक साथियों से अधिक से अधिक संख्या में सम्मेलन में उपस्थित होकर शासन की श्रमिक हितैषी योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी कार्यक्रम में शामिल होकर श्रमिक सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की है।यह आयोजन श्रमिकों के हित में शासन द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को उनकी पात्रता की सभी योजनाओं का वास्तविक लाभ उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को दिया आत्मविश्वास और सफलता का संदेश

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा — ऑल द बेस्ट, प्यारे बच्चों। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के छात्र-छात्राओं को परीक्षाओं के अवसर पर शुभकामनाएँ देते हुए उन्हें आत्मविश्वास और हौसले के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया है। उन्होंने विद्यार्थियों के नाम अपने आत्मीय संदेश में कहा कि परीक्षाओं का समय जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जिसमें उत्साह के साथ थोड़ा तनाव भी स्वाभाविक है, लेकिन

घबराने की आवश्यकता नहीं है।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि परीक्षाओं का समय आ गया है। मैं जानता हूँ कि इन दिनों आपके मन में उत्साह भी है और थोड़ा सा तनाव भी। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए — आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं।

उन्होंने कहा कि परीक्षाओं का समय कभी-कभी मन में घबराहट भी लेकर आता है। यह स्वाभाविक है। यदि आपको डर लग रहा है तो इसका अर्थ है कि आप अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य को गंभीरता से लेते हैं।

उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह समझ लीजिए — डर कमजोरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का संकेत है। लेकिन इस डर को अपने आत्मविश्वास पर हावी न होने दें। आपने पूरे वर्ष मेहनत की है। हर दिन का प्रयास, हर अभ्यास, हर दोहराव — सब आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़े हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी नियमित पढ़ाई करें, कठिन विषयों को दोहराएँ, समय का संतुलन बनाए रखें। पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन करें और कुछ समय के लिए मोबाइल से दूरी बनाकर अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ के सभी विद्यार्थी इस बार भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और अपने परिवार तथा प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, रायपुर छत्तीसगढ़

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्र. 112/नि.शा./ का.अ./ लो.स्वा.यां./ खण्ड, रायपुर, दिनांक 06.02.2026

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

स. क्र.	कार्य का नाम	राशि (रू. लाख में)
1	रायपुर जिले के विकासखंड तिल्दा के ग्राम खौलीडबरी जलप्रदाय योजना के अंतर्गत शिफ्टिंग कार्य हेतु राईजिंग मेन में 90mm dia 10kg/cm² के UPVC पाईप 500 मीटर, 100 मि.मी. व्यास के जी.आई. पाईप 30 मीटर का प्रदाय कर बिछाने, जोड़ने, परीक्षण कर चालू करने का कार्य।	7.24

उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति व अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20.02.2026 सायं 5.30 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड,
रायपुर छत्तीसगढ़

जी-252606712/3

विकास की धड़कन बना असम ब्रह्मपुत्र पर सेतु

कांतिलाल मांडोत

असम की धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी की जनसभा में भारत माता की जय का उद्घोष किया, तो वह केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि उत्तर-पूर्व के विकास को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का संदेश भी था। उनके संबोधन में संगठन की शक्ति, कार्यकर्ताओं के समर्पण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प की झलक दिखाई दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2014 के बाद उत्तर-पूर्व को प्राथमिकता दी गई है और यह क्षेत्र अब विकास की मुख्यधारा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम, जो लंबे समय तक भौगोलिक दूरी और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण पिछड़ा माना जाता था, आज बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए नए युग में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 6-लेन के आधुनिक पुल कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। लगभग 3,030 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह पुल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ता है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्राडोज्ड पुल है, जो इंजीनियरिंग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बन जाने से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर मात्र सात मिनट रह जाएगा। इससे न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। ब्रह्मपुत्र, जो असम की जीवनरेखा है, अब विकास का सेतु बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी उल्लेख किया कि पिछले वर्षों में उत्तरङ्कपूर्व के 125 से अधिक महान व्यक्तित्वों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र की प्रतिभा और सांस्कृतिक समृद्धि को राष्ट्रीय मंच पर उचित पहचान मिल रही है। लंबे समय तक उपेक्षित रहे इस भूभाग को अब देश के विकास मानचित्र में प्रमुख स्थान दिया जा रहा है। विकास की इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर रेल एवं सड़क टनल को मंजूरी दी है। यह परियोजना गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच बनाई जाएगी। लगभग 15.8 किलोमीटर लंबी यह टनल तकनीकी दृष्टि से अत्यंत जटिल और महत्वाकांक्षी है। पूरे प्रोजेक्ट, जिसमें अप्रोच रोड और रेलवे ट्रैक भी शामिल हैं, की लंबाई 33.7 किलोमीटर होगी और इस पर लगभग 18,600 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस टनल के बन जाने से वर्तमान में 240 किलोमीटर की दूरी घटकर लगभग 34 किलोमीटर रह जाएगी। इससे न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क भी सुदृढ़ होगा। यह परियोजना सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपात स्थिति में सेना और आवश्यक संसाधनों की तेजी से आवाजाही संभव हो सकेगी। एक ट्यूब में सिंगल रेल ट्रैक की सुविधा होगी और ट्रेनें बिजली से संचालित होंगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि ट्रेन के गुजरने के दौरान सड़क यातायात नियंत्रित रहेगा। इसमें बैलिस्टिक ट्रैक जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो इसे अत्याधुनिक संरचना बनाता है। इन परियोजनाओं का महत्व केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है। उत्तर-पूर्व भारत लंबे समय से भौगोलिक अलगाव और सीमित बुनियादी ढांचे के कारण आर्थिक रूप से पीछे रहा है। जब मजबूत पुल, आधुनिक सड़कें और सुरक्षित रेल नेटवर्क तैयार होते हैं, तो वे केवल दो स्थानों को नहीं जोड़ते, बल्कि संभावनाओं को जोड़ते हैं। इससे उद्योग, कृषि, पर्यटन और छोटे व्यवसायों को नई ऊर्जा मिलती है।

भारत में एआई का वैश्विक महाकुंभ

किशन सनमुखदास भावनानीं

वैश्विक स्तरपर 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने भारत को वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिदृश्य के केंद्र में स्थापित कर दिया है। नई दिल्ली में आयोजित यह पाँच दिवसीय महाकुंभ केवल एक तकनीकी सम्मेलन नहीं, बल्कि भविष्य की विश्व व्यवस्था को आकार देने वाला मंच बनकर उभरा है। इस समिट के साथ आयोजित एआई एक्सपो में लगभग 65 देशों की भागीदारी, 600 से अधिक स्टार्टअप्स की उपस्थिति 13 देशों केपवेलियन 2.5 लाख से अधिक संभावित आगंतुक, 500 से अधिक सत्र और 3250 से अधिक वक्ता एवं पैनल सदस्य शामिल हो रहे हैं,जो वैश्विक स्तरपर रेखांकित करने वाली बात है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह आयोजन भारत के तकनीकी आत्मविश्वास, कूटनीतिक परिपक्वता और नवाचार-नेतृत्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तरपर एआई को लेकर दो प्रमुख विमर्श सामने आ सकते हैं,एक ओर विनाशकारी जोखिम, नियामक ढांचा और नैतिकता; तो दूसरी ओर नवाचार, समावेशन और विकास। भारत इस समिट के माध्यम से इन दोनों ध्रुवों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।जहाँ पूर्ववर्ती वैश्विक चर्चाएँअधिकतर जोखिमों और नियंत्रण पर केंद्रित थीं, वहीं नई दिल्ली इस बहस को जिम्मेदार,समावेशी और विकासोन्मुख एआई की दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रही है। यह बदलाव केवल शब्दों का नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का है एआई को भय का नहीं, बल्कि अवसर का माध्यम मानने का दृष्टिकोण।

साथियों बात कर हम इस महत्वपूर्ण समिट को समझने की करें तो समिट का उद्घाटन 16 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शाम 5 बजे एआई एक्सपो के उद्घाटन के साथ हुआ। उद्घाटन समारोह में उन्होंने एआई को मानवता के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बताते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य केवल तकनीकी उपभोक्ता बनना नहीं, बल्कि वैश्विक एआई आर्किटेक्चर के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनना है। उनके संबोधन में यह स्पष्ट संदेश था कि भारत एआई को लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और सतत विकास के

साथ जोड़कर आगे बढ़ाना चाहता है।एआई एक्सपो इस समिट का जीवंत और व्यावहारिक आयाम है। यहाँ विश्व की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियाँ,उभरते स्टार्टअप्स, विश्वविद्यालय,अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और अंतरराष्ट्रीय साझेदार एक ही मंच पर उपस्थित हैं।13 देशों के पवेलियन ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया ताजिकिस्तान और अफ्रीका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एआई इकोसिस्टम में वैश्विक सहयोग की भावना को दर्शाते हैं। ये पवेलियन केवल प्रदर्शनी स्थल नहीं, बल्कि तकनीकी साझेदारी,निवेश अवसर और नीति संवाद केएक प्रमुख केंद्र बन गए हैं।

साथियों बात अगर हम इस सबमिट की रूपरेखा को समझने की करें तो, 17 फरवरी को समिट का दूसरा दिन एप्लाइड एआई पर केंद्रित होगा।स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि,महिला सशक्तिकरण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग पर विस्तृत चर्चाएँ होंगी।स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई आधारित डायग्नोस्टिक्स, टेलीमेडिसिन और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की संभावनाओं पर विचार किया जायेगा।ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड और कार्बन उत्सर्जन मॉनिटरिंग पर एआई के उपयोग को रेखांकित किया गया।शिक्षा में व्यक्तिगत सीखने (पर्सनलाइज्ड लर्निंग) और एआई ट्यूटरिंग सिस्टम्स की संभावनाएँ सामने होंगी । कृषि में प्रिसीजन फार्मिंग, मौसम पूर्वानुमान और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन जैसे उदाहरण प्रस्तुत हो सकते हैं। इस दिन प्रमुख नॉलेज कम्पेंडियम्स और केसबुक्स भी जारी होंगें , जो नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोगी होंगे।18 फरवरी को आयोजित रिसर्च सिम्पोज़ियम और इंडस्ट्री सेशन ने अनुसंधान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच पुल का कार्य होगा।शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंकों ने अत्याधुनिक एआई अनुसंधान, उभरती पद्धतियों और साक्ष्य- आधारित नीति अंतर्दृष्टि प्रस्तुत होंगी।इस मंच पर एआई मॉडल की पारदर्शिता,एल्गोरिदमिक बायस, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गहन विमर्श होगा।यह स्पष्ट होगा कि एआई का भविष्य केवल तकनीकी दक्षता पर निर्भर नहीं, बल्कि नैतिकता और जवाबदेही पर भी आधारित होगा।19 फरवरी को 20 से अधिक देशों के नेताओं की उपस्थिति ने इस समिट को वैश्विक राजनीतिक महत्व प्रदान किया जायेगा। इस दिन एआई पर सामूहिक प्रतिबद्धताओं, वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करने और आने वाले एआई दशक में भारत की भूमिका को परिभाषित करने पर चर्चा होंगी। उच्च- स्तरीय सीईओ राउंडटेबल में वैश्विक उद्योग नेताओं, निवेशकों और नीति निर्माताओं ने जिम्मेदार एआई के भविष्य पर विचार-विमर्श जायेगा।यहाँ यह स्वीकार किया गया कि एआई से रोजगार के स्वरूप में बदलाव आएगा, परंतु साथ ही नई नौकरियों और कौशलों की मांग भी उत्पन्न होगी। साथियों बात अगर हम रोजगार का प्रश्न इस समिट के माध्यम से समझने की करें तो यह केंद्रीय चिंता होंगी.कई वैश्विक सीईओ और एआई शोधकर्ताओं ने पहले ही चेतावनी दी है कि ऑटोमेशन और जनरेटिव एआई के कारण पारंपरिक नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। परंतु समिट में यह भी रेखांकित किया जा सकता है कि एआई डेटा साइंस,मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग साइबर सुरक्षा, एआई एथिक्स और मानव- एआई सहयोग जैसे क्षेत्रों में नई नौकरियाँ सृजित करेगा। भारत जैसे युवा देश के लिए यह अवसर है कि वह कौशल विकास और शिक्षा प्रणाली में सुधार कर इस परिवर्तन को सकारात्मक दिशा दे।

साथियों बात अगर हम एआई और सुरक्षा का मुद्दा इसको समझने की करें तो यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठा सकता है, साइबर हमले,डीपफेक, डेटा दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की। इस संदर्भ में बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया जायेगा।एआई के सैन्य उपयोग और स्वायत्त हथियार प्रणालियों पर भी विचार होगा,जिसमें जिम्मेदार उपयोग और अंतरराष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता को रेखांकित किया जायेगा डेटा सेंटर और पर्यावरणीय प्रभाव का प्रश्न भी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय होगा। बड़े-बड़े डेटा सेंटर ऊर्जा की भारी खपत करते हैं और कार्बन उत्सर्जन बढ़ा सकते हैं। समिट में ग्रीन एआई, ऊर्जा-कुशल चिप्स और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित डेटा सेंटर की अवधारणा पर विचार किया जा सकता है।यह स्पष्ट होगा कि तकनीकी प्रगति को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करना अनिवार्य है। 20 फरवरी को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशल इंटेलीजेंस (जीपीएआई) परिषद की उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित होंगी।सदस्य देशों केप्रतिनिधियों ने एआई पर सहयोग बढ़ाने की प्रगति की समीक्षा की और जिम्मेदार एवं समावेशी एआई के लिए नए बहुपक्षीय विकल्पों पर विचार होगा।बैठक के अंत में लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाया गया,जिसमें सामूहिक प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए वैश्विक एआई शासन और सहयोग के लिए साझा रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी।यह समिट भारत की डिजिटल कूटनीति का भी उदाहरण है। भारत ने स्वयं को केवल तकनीकी बाजार के रूप में नहीं, बल्कि नीति निर्माता और वैश्विक संवादकर्ता के रूप में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।एआई के भविष्य को आकार देने में भारत की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ विशाल डेटा संसाधन,युवा प्रतिभा और तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम मौजूद है।इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने यह स्पष्ट कर देगा कि एआई केवल तकनीकी नवाचार नहीं,बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम है।भारत ने इस मंच के माध्यम से दुनियाँ को यह संदेश देगा कि एआई का भविष्य भय और नियंत्रण की सीमाओं में नहीं, बल्कि सहयोग, समावेशन और सतत विकास की दिशा में होना चाहिए।

अत: अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि यह समिट एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में देखा जाएगा, जहाँ भारत ने न केवल तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन होगा, बल्कि वैश्विक एआई विमर्श को नई दिशा देने का साहस भी दिखेगा । आने वाले वर्षों में जब एआई मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा, तब 16-20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित यह महाकुंभ उस परिवर्तनकारी यात्रा की आधारशिला के रूप में स्मरण किया जाएगा।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

(छ) सोमस्य वा अभिषूयमाणस्य प्रियातनूरुदक्रामत् तत्सुवर्ण हिरण्यमभवत्।

(तैत्तिरीय 1।4.7।4-5)

अर्थात् (क) प्रजा के पालक विष्णु भगवान् अप्सरा का रूप बनाकर [शिव जी के आगे प्रकट हुवे। (ख) इस विष्णु के रमणीय शरीर में देवताओं ने रमण किया इसलिए हि-रम्य शब्द से हिरण्य शब्द की प्रवृत्ति हुई, अर्थात् हि-रम्य को ही परोक्ष रीति से हिरण्य ऐसा कहते हैं। (ग) अग्नि ने जलों का ध्यान किया कि मैं इनसे मिथुनी भाव को प्राप्त हूं वे प्रकट हुवे, अग्नि ने उनमें वीर्य सेचन किया वह हिरण्य-सोना बन गया। (घ) उस [शिव जी का रेत: = वीर्य गिर पड़ा वह सोना बन गया। (ङ) इस हिरण्य-सुवर्ण का तीन प्रकार से जन्म हुआ है पहिला अग्नि का प्यारा हुया दूसरा-सोम के मारने से गिरा, तीसरा सृष्टि विधायक जलों का रेत:- वीर्य कहा जाता है। (च) अग्नि का रेत:- वीर्य ही हिरण्य सुवर्ण है। (छ) सम्पादन करते हुवे सोम का प्यारा शरीर (वीर्य) निकल पड़ा वह सुवर्ण-हिरण्य बन गया ।

पौराणिक-स्वरूप

कौतुहलाय दैत्यानां, योषिद्वेशो मया कृत: ।।15।।
तत्तेहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षो: सुरसत्तम ! ।। 16।।
इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत ।।17।।
एवं तां रुचिरापांगी, दर्शनीयां भनोरमाम् ।।
दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विषज्जन्त्यां भव: किल । 24।।
तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दामोघरेतस: ।।32॥
तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन्महीपते! ।। 33।।

(श्रीमद्भागवत 8 । 12 । 15-33)

अर्थात्- शिव जी की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान् ने कहा- कि हे देवाधिदेव महादेव ! दैत्यों को चकित करने के लिये मैंने स्त्री रूप धारण किया था मैं वही आपको दिखलाऊंगा ।। 15-16 ।।

क्रमशः...

मानवता के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस

रमेश सर्राफ धमोरा

स्वामी रामकृष्ण परमहंस भारत के सुप्रसिद्ध संत, महान विचारक व मानवता के पुजारी थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने सभी धर्मो को एक बताते हुए उनकी एकता पर जोर दिया था। उनका मानना था सभी धर्मो का आधार प्रेम हैं। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति की। अपनी साधना से रामकृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। वे ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न-भिन्न साधन मात्र हैं।

इनका जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकुर नामक गांव में 18 फरवरी 1836 को एक निर्धन निष्ठावान ब्राहमण परिवार में हुआ था। इनके जन्म पर ही ज्योतिषियों ने रामकृष्ण के महान भविष्य की घोषणा कर दी थी। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुन इनकी माता चन्द्रा देवी तथा पिता खुदिराम अत्यन्त प्रसन्न हुए। इनको बचपन में गदाधर नाम से पुकारा जाता था। पांच वर्ष की उम्र में ही वो अदभुत प्रतिभा और स्मरणशक्ति का परिचय देने लगे। अपने पूर्वजों के नाम व देवी- देवताओं की स्तुतियां, रामायण, महाभारत की कथायें इन्हे कंठस्थ याद हो गई थी।

रामकृष्ण के जीवन में अनेक गुरु आये पर अन्तिम गुरुओं का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। एक थी भैरवी जिन्होने उन्हे अपने कापालिक तंत्र की साधना करायी और दूसरे थे श्री तोतापुरी उनके अन्तिम गुरु। गंगा के तट पर दक्षिणेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में रहकर रामकृष्ण मां काली की पूजा किया करते थे। गंगा नदी के दूसरे किनारे रहने वाली भैरवी को अनुभुति हुई कि एक महान संस्कारी व्यक्ति रामकृष्ण को उसकी दीक्षा की आवश्यकता हैं। गंगा पार कर वो रामकृष्ण के पास आयी तथा उन्हे कापालिक दीक्षा लेने को कहा। रामकृष्ण ने भैरवी द्वारा बतायी पद्धति से लगातार साधना कर मात्र तीन दिनों में ही सम्पूर्ण क्रिया में निपुण हो गये।

रामकृष्ण के अन्तिम गुरु तोतापुरी थे जो सिद्ध तांत्रिक तथा हठ योगी थे। उन्होने रामकृष्ण को दीक्षा दी। रामकृष्ण को दीक्षा दी गई परमशिव के निराकार रुप के साथ पूर्ण संयोग की। पर आजीवन तो उन्होने मां काली की आराधना की थी। वे जब भी ध्यान करते तो मां काली उनके ध्यान में आ जाती और वे भावविभोर हो जाते। जिससे निराकार का ध्यान उनसे नहीं हो पाता था।

रामकृष्ण परमहंस महान योगी, उच्चकोटि के साधक व विचारक थे। सेवा पथ को ईश्वरीय, प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। सेवा से समाज की सुरक्षा चाहते थे। रामकृष्ण का सारा जीवन अध्यात्म-साधना के प्रयोगों में बीता।

इनके प्रमुख शिष्यों में स्वामी विवेकानन्द, दुर्गाचरण नाग, स्वामी अद्भुतानंद, स्वामी ब्रह्मानंदन, स्वामी अद्यतानन्द, स्वामी शिवानन्द, स्वामी प्रेमानन्द, स्वामी योगानन्द थे। श्री रामकृष्ण के जीवन के अन्तिम वर्ष कारुण रस से भरे थे। 15 अगस्त 1886 को अपने भक्तों और स्नेहितों को दुख के सागर में डुबाकर वे इस लोक में महाप्रयाण कर गये।

भारत और यूरोप क्यों आ रहे हैं एक साथ?

शेखर गुप्ता

यह एक ऐसा खेल है जिसे सीखने का प्रयास अब दुनिया का हर देश कर रहा है। वे कुछ नए सहयोगी तलाश रहे हैं या उन देशों में मूल्य देख रहे हैं जिनमें पहले उनकी रुचि न के बराबर थी।

आज की भू-राजनीति में असली खेल शक्ति जुटाने और अपने लिए समय हासिल करने का है। यह किन्हीं दो देशों के बीच का मुकाबला नहीं है। आपके पास जितनी अधिक ताकत की गुंजाइश होगी आपके पास उतना ही अधिक समय होगा। कोई भी महत्त्वपूर्ण देश जो संप्रभु देश हो, भले वह कितना भी छोटा क्यों न हो, यही खेल खेल रहा है। भारत इस समीकरण में कहां खड़ा है। हम इस बारे में बात करेंगे।

लसूटू के बारे में सोचिए जिसकी आबादी महज 23 लाख है। यह पहाड़ी देश चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। वहां बहुत अधिक गरीबी है और यह दुनिया के सबसे अधिक एचआईवी ग्रस्त देशों में है। उसकी प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान से भी आधी है। लेकिन उसके पास एक खास औद्योगिक शक्ति है। उसे दुनिया की जींस हब कहा जाता है। वस्त्र उद्योग उसका सबसे बड़ा रोजगार तैयार करने वाला क्षेत्र है जिसमें करीब 50,000 लोग काम करते हैं। अधिकांश निर्यात अमेरिका को किया जाता है। यह लेसेथो के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 10 फीसदी है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि अफ्रीकन ग्रोथ ऐंड अपॉर्च्युनिटी (एजीएओ) के तहत उसे अमेरिका में शुल्क मुक्त पहुंच मिली है।

उसके बाद 2025 में डॉनल्ड ट्रंप आए और एजीएओ को भूल गए। लेसेथो पर 50 फीसदी का शुल्क लगा दिया गया जिसे बाद में घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया। लेसेथो बड़े एशियाई विनिर्माताओं मसलन बांग्लादेश, वियतनाम और भारत की तुलना में प्रतिस्पर्धा से पिछड़ गया। अब उसने आधिकारिक तौर पर आपदाकाल घोषित कर दिया है। लेसेथो को एक ऐसे देश के उदाहरण के

रूप में लेते हैं जिसके पास न तो ताकत है और न ही समय। उसकी अर्थव्यवस्था ट्रंप का इंतजार नहीं कर सकती। अब बात करते हैं उस देश की जिसके पास सबसे अधिक ताकत और समय है, यानी चीन। कारोबार के क्षेत्र में चीन अहम खनिजों की बिक्री और सोया और मक्के के खरीदार के रूप में ताकत रखता है। उसकी सेना तेजी से अमेरिका की तरह मजबूती हासिल कर रही है। दूसरी तरफ, ट्रंप अमेरिकी गठबंधनों को कमजोर कर रहे हैं।

और उसका समय केवल ट्रंप के तीन वर्षों तक सीमित नहीं है। यह उसके लिए अवसर का समय है। जैसे ही परेशान अमेरिका रणनीतिक दबाव कम करता है, चीन खुद को इतना मजबूत कर लेगा कि ट्रंप के उत्तराधिकारी शायद कभी इसकी बराबरी न कर सकें। अगर लेसेथो सबसे कमजोर देश का और चीन शीर्ष देश का उदाहरण है तो बाकियों का क्या? यूरोप की दिक्कतों और लसूटू के संकट को एक साथ तौलना अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोप को इसका एहसास पिछले दिनों म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हुआ, जब उसे लगा कि उसकी अपनी ताकत कम है और वह सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। अब वे सुरक्षा पर खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन खुद को सुरक्षित महसूस करने में उन्हें कई साल लगेंगे।

हथियार प्रणाली, खासतौर पर लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, मिसाइल यहां तक कि बुनियादी 155 मिमी तोप आदि को हैमलीज या एमेजॉन से ऑर्डर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आपको ऐसे नागरिक भी तलाश करने होते हैं जो लड़ने के इच्छुक हों। उन्हें प्रशिक्षण भी देना होगा। ऐसे में जाहिर है पुतिन के खतरे को देखते हुए उनके पास समय नहीं है।

हम चीन को अमेरिका से ऊपर कैसे रख सकते हैं? अमेरिका अभी भी चीन से अधिक ताकतवर है लेकिन उसका समय ट्रंप के शेष तीन वर्षों तक सीमित है। अमेरिका सभी अन्य देशों के निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार है और उसके पास शुल्क लगाने की शक्ति है। उसके पास सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है और आठ दशकों से उसके सबसे वफादार सहयोगी हैं। यूरोप, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान उस पर निर्भर हैं। अर्ध सहयोगी या रणनीतिक साझेदार, जिनमें भारत भी शामिल है, एक उभरते चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका की आवश्यकता रखते हैं।

उसके पास बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, एआई क्षेत्र का नेतृत्व है और वैश्विक रिजर्व करेंसी भी है। लेकिन ट्रंप इनमें निवेश के बजाय इन्हें खर्च कर रहे हैं। अमेरिका की ताकत कमजोर पड़ रही है।

तीन साल बाद शायद वह एक अलग महाशक्ति होगा। क्या वह चीन के हाथों अपनी शक्ति गंवा चुका होगा? क्या उसके सहयोगी दोबारा उस पर भरोसा करेंगे? एक नाम याद रखिए- यूक्रेन नहीं ग्रीनलैंड। अमेरिकी साझेदारों को यह चिंता होगी कि अगर कल को अमेरिका में कोई और ज्यादा असहज करने वाला नेता सामने आ गया तो? अमेरिका के पास यही तीन साल का समय है यानी अगले चुनाव तक का। या सिर्फ 10 महीने भी हो सकता है, अगर मध्यावधि चुनाव ने ट्रंप को कमजोर कर दिया। यह एक महत्त्वपूर्ण बात दिखाता है। लोकतांत्रिक देशों के पास सीमित समय होता है।

अगले चार से पांच साल में इन सभी देशों में चुनाव होंगे। इजरायल की ताकत उसके इतिहास, विचारधारा, बौद्धिकता, भू-आर्थिकी, सेना और खुफिया शक्ति से आती है। वह एक पश्चिमी लोकतंत्र है जो एशिया और अफ्रीका के मुहाने पर है। वह यूरोप, अमेरिका और भारत का अनिवार्य सहयोगी है। हालांकि किसी चुनाव के बाद या अदालती कार्रवाई के चलते बेंजामिन नेतन्याहू को जाना होगा। तब शायद एक अलग इजरायल नजर आए। समय की सीमा लोकतंत्र का एक खास गुण है।

यह शी चिनफिंग, व्लादीमिर पुतिन और आजीवन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर लागू नहीं होता। उत्तर कोरिया जैसी विशुद्ध तानाशाही हो या पाकिस्तान जैसी मिलीजुली तानाशाही, वहां समय की सीमा नहीं होती। हालांकि, ऐसे देशों में अचानक बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन हम भविष्य नहीं बता सकते।

अब हर देश यह खेल खेलना सीख रहा है। कुछ को नए साझेदार मिल रहे हैं या ऐसे देशों में मूल्य दिख रहा है जिनमें पहले नहीं दिखता था। इसका सबसे सटीक उदाहरण है भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता। इस बदली हुई दुनिया ने भारत को ज्यादा मुक्त और प्रतिस्पर्धी बाजार के फायदे देखने को विवश किया है। रूस, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि सभी इस परिदृश्य में अपने आप को ढाल रहे हैं। इन पैमानों पर भारत कहां है? तथ्य यह है कि भारत की शक्ति सीमित है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने यह देखा जब हमारे 32 रणनीतिक साझेदारों सहित लगभग पूरी दुनिया में से बहुत कम देश हमारे साथ नजर आए।

इसकी वजह हमारी अर्थव्यवस्था और बाजार हैं। ताकत बढ़ाने के लिए हमें जीडीपी को बढ़ाना होगा। उसके लिए अधिक जोखिम भरे सुधार करने होंगे, बाजार खोलने होंगे। मौजूदा आकार और दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होना बेमानी होगा अगर हम दुनिया को यह यकीन नहीं दिला पाए कि हम अगले एक दशक तक 7.5 फीसदी सालाना की दर से वृद्धि हासिल करते रहेंगे।

आज का इतिहास

1952 ग्रीस और तुर्की उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हुए।
1957 केन्या के स्वतंत्रता नेता ददन किमाथी, जिन्होंने माउ माउ विद्रोह की अगुवाई की थी, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निष्पादित किया गया था, जिन्होंने उन्हें एक आतंकवादी के रूप में देखा था।
1965 गाम्बिया देश को ब्रिटेन से स्वाधीनता मिली और आज के दिन को इस देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया।
1970 एक अमेरिकी जूरी ने 1968 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान विरोध प्रदर्शनों से दंगों को भड़काने की साजिश के शिकागो सेवन को बरी कर दिया।
1977 नासा के पहले स्पेस शटल, एंटरप्राइज ने बोइंग 747 शटल कैरियर एयरक्राफ्ट के साथ अपनी पहली उड़ान बनाई।
1977 ब्रिटिश साइंस फिक्शन कॉमिक 2000 एडी की शुरुआत, प्रोजे 1 के साथ 26 फरवरी को की गई।
1991 एडमॉन्टन ऑइल गोलकीपर ग्रांट फुहर एनएफएल में लौटते हैं। मादक द्रव्यों के सेवन के लिए उन्हें एक लंबे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। 18 फरवरी, 1991 को उन्होंने न्यू जर्सी डेविल्स को 4-0 से हरा दिया।
1994 अभिनेता जो पैंटोलियानो और मॉडल नैंसी शिपर्ड की शादी फरवरी 1994 में हुई थी। उनकी शादी के दौरान जो 41 साल की थीं, जबकि नैंसी 31 साल की थीं।
1995 बार्ब जोन्स व्हाइटहेड ने 18 फरवरी, 1995 को कप ओ नूडल्स हवाईयन लेडीज गोल्फ ओपन जीता।
2001 एफबीआई एजेंट रॉबर्ट हैनससेन गिरफ्तार किया गया क्यूंकि 25 साल के लिए रूस की जासूसी करने का आरोप था।
2003 आगजनी में दक्षिण कोरिया के डेगू में एक रेलवे स्टेशन में आग लग गई, इस घटना में लगभग 200 लोग मारे गए।
2010 रिबेल्स ने नाइजी के नाइमी में राष्ट्रपति महल पर हमला किया, और राष्ट्रपति ममदौ तंदजा की जगह एक सत्तारूढ़ जुंटा, लोकतंत्र की बहाली के लिए सर्वोच्च परिषद।
2011 युगांडा के मतदाता आम चुनाव में भाग लेते हैं। मतदाता फ़ेसर का कहना है कि चुनाव में धांधली की गई है ताकि 30 साल के विद्रोही युरी मुसेवेनी शासन करें।
2012 पोप बेनेडिक्ट सोलहवें ने सात नए संतों की घोषणा की। संतों में अमेरिकी संत, कटेरी टेकविथा शामिल थे। वह बाईस नए कार्डिनल भी नियुक्त करता है।
2013 नेस्ले कंपनी ने अपने बीफ पास्ता को फ्रांस, स्पेन और इटली में मौजूद सुपरमार्केट से हटाने का फैसला किया है। परीक्षणों के बाद पता चलता है कि फूड जायंट में ऐसे उत्पाद हैं जो हॉर्समेट से दूषित हैं।

बंगाल का भविष्य : धर्म की लहर या प्रगति की राह?

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी बाकी हो, पर राजनीतिक रणभेरी बज चुकी है। इस बार संकेत साफ हैं-चुनाव विकास बनाम विकास के दावे पर नहीं, बल्कि पहचान, अस्मिता और धर्म की ध्वजा के इर्द-गिर्द घूम सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य भर में प्रस्तावित हिंदू सम्मेलनों को भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक उत्सव भर नहीं, बल्कि चुनावी अवसर में बदलने की रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी यह समझ लिया है कि यदि चुनाव की जमीन धार्मिक विमर्श पर खिसकती है तो उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोलकाता के न्यू टाउन में 'दुर्गा आंगन' का शिलान्यास और उसे बंगाली अस्मिता से जोड़ने का प्रयास इसी रणनीतिक सजगता का हिस्सा है।

बंगाल की राजनीति लंबे समय तक वर्ग-संघर्ष, वाम वैचारिकी और सामाजिक न्याय के नारों के इर्द-गिर्द घूमती रही। लगभग तीन दशक तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में वाम मोर्चा सत्ता में रहा। उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व था। किंतु 2011 में सत्ता परिवर्तन के साथ एक नई धुरी बनी-तृणमूल बनाम भाजपा। आज स्थिति यह है कि वाम और कांग्रेस हाशिए पर हैं और मुकाबला दो ध्रुवों के बीच सिमट चुका है। यही द्विध्रुवीयता चुनाव को अधिक तीखा और अधिक पहचान-केन्द्रित बना रही है। भाजपा का अभियान चार प्रमुख सूत्रों पर टिका है-बंगाल में हिंदू खतरे में है, बांग्लादेशी घुसपैठ, महिलाओं की असुरक्षा और भ्रष्टाचार। सीमावर्ती जिलों का उदाहरण देकर यह संदेश गढ़ा जा रहा है कि जनसांख्यिकीय संतुलन बदल रहा है। अवैध घुसपैठ का प्रश्न नया नहीं है, पर उसे इस समय राजनीतिक ऊर्जा के साथ जोड़ा जा रहा है। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की घटना, शिक्षक भर्ती घोटाले, हिन्दुओं पर बढ़ते अत्याचार एवं भ्रष्टाचार जैसे प्रसंगों को शासन की विफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य स्पष्ट है-70 प्रतिशत हिंदू मतदाताओं में एक साझा असुरक्षा-बोध निर्मित करना, हिन्दुओं को जागृत करना और उसे मतदान व्यवहार में रूपांतरित करना। आज बंगाल में विकास की सबसे बड़ी बाधा घुसपैठियों का बढ़ना है। घुसपैठियों पर विराम लगाना चाहिए न कि इस मुद्दे पर राजनीति हो।

ममता बनर्जी की चुनौती दोहरी है। एक ओर उन्हें यह संदेश देना है कि वे अल्पसंख्यकों की संरक्षक हैं, दूसरी ओर हिंदू मतदाताओं को यह विश्वास भी दिलाना है कि उनकी आस्था और अस्मिता सुरक्षित है। 2021 के चुनाव में जब भाजपा ने 'जय श्रीराम' के नारे को आक्रामक रूप से उछाला, तब ममता ने 'जय मां दुर्गा' और 'चंडी पाठ' के माध्यम से एक सांस्कृतिक प्रत्युत्तर दिया था। इस बार वे दुर्गा आंगन जैसे प्रतीकों के जरिए यह संकेत दे रही हैं कि बंगाली हिंदू पहचान भाजपा की बपौती

नहीं है। वे धर्म को राष्ट्रवाद की बजाय क्षेत्रीय अस्मिता के साथ जोड़ती हैं-बंगाल अपनी संस्कृति से हिंदू है, पर उसकी राजनीति बहुलतावादी है-यह उनका अंतर्निहित संदेश है। इसी बीच मुर्शिदाबाद में पूर्व तृणमूल नेता हुमायूं कबीर द्वारा 'बाबरी मस्जिद' के शिलान्यास की पहल ने नई जटिलता जोड़ दी है। इससे मुस्लिम मतदाताओं के भीतर एक अलग ध्रुवीकरण की संभावना पैदा हुई है। यदि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है, तो तृणमूल का गणित प्रभावित हो सकती है। 2021 में उसे लगभग 48 प्रतिशत वोट और 223 सीटें मिली थीं-जिसमें मुस्लिम मतों का एकमुश्त समर्थन निर्णायक था। भाजपा 38 प्रतिशत वोट के साथ 65 सीटें जीतकर मुख्य विपक्ष बनी। ऐसे में यदि मुस्लिम मत 5-10 प्रतिशत भी इधर-उधर खिसकते हैं, तो कई सीटों का परिणाम बदल सकता है और भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ सकती है।

यहां प्रश्न केवल गणित का नहीं, राजनीति के चरित्र का भी है। क्या बंगाल का चुनाव धार्मिक पहचान के उभार का प्रयोगशाला बनेगा? या यह प्रयोग अंतत: विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे के प्रश्नों पर लौटेगा? विडंबना यह है कि जिस बंगाल को कभी देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता था-जहां से उद्योग, शिक्षा और सांस्कृतिक नवजागरण की रोशनी फैलती थी, वह आज अधूरे प्रोजेक्ट्स, धीमी औद्योगिक गति और रोजगार के पलायन से जूझ रहा है। कोलकाता की सड़कों पर अधूरी मेट्रो लाइनें और बंद कारखानों की चुप्पी विकास की उस कहानी को बयान करती हैं, जो राजनीतिक नारों के शोर में दब जाती है। 2011 में टाटा के नैनो प्रोजेक्ट का राज्य से बाहर जाना एक प्रतीकात्मक मोड़ था। भूमि अधिग्रहण के प्रश्न पर जनसमर्थन पाने वाली राजनीति ने उद्योग के प्रति संशय का वातावरण भी बनाया। पंद्रह वर्षों बाद भी बंगाल बड़े निवेश की प्रतीक्षा में है। युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, और कई राज्यों में उन्हें 'बांग्लादेशी' कहकर अपमानित किए जाने की खबरें आती हैं। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, आत्मसम्मान का प्रश्न भी है। किंतु चुनावी विमर्श में यह पीड़ा गौण हो जाती है, और केंद्र में आ जाता है-धर्म, पहचान और भय।

ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाती हैं; भाजपा राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का। सी.बी.आई. और ई.डी. की कार्रवाइयों को ममता राजनीतिक प्रतिशोध बताती हैं, जबकि भाजपा उन्हें कानून का पालन। इस टकराव ने प्रशासनिक संवाद को भी राजनीतिक संघर्ष में बदल दिया है। परिणाम यह है कि विकास का एजेंडा आरोप-प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या धर्म-आधारित ध्रुवीकरण स्थायी राजनीतिक समाधान दे सकता है? इतिहास बताता है कि धार्मिक उभार अल्पकालिक ऊर्जा तो देता है, पर दीर्घकालिक शासन-क्षमता की कसौटी पर उसे विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रश्नों से जूझना ही पड़ता है। यदि चुनाव केवल कौन किसका प्रतिनिधि है तक सीमित रह गया, तो कौन क्या करेगा का प्रश्न अनुत्तरित रह जाएगा।

बंगाल की आत्मा बहुलतावाद में रही है-रामकृष्ण परमहंस से लेकर रवींद्रनाथ तक, यह भूमि विविध आस्थाओं और विचारों का संगम रही है। यहां दुर्गा पूजा और मुहर्रम दोनों सामाजिक उत्सव का रूप लेते रहे हैं। यदि राजनीति इस सामाजिक ताने-बाने को चुनावी अंकगणित में बदल देगी, तो समाज की संवेदनशीलता पर चोट पहुंचेगी। दूसरी ओर, यदि धार्मिक प्रतीकों का उपयोग सांस्कृतिक आत्मगौरव के साथ विकास-प्रतिबद्धता को जोड़ने में किया जाए, तो वह सकारात्मक भी हो सकता है। इस चुनाव में भाजपा की रणनीति हिंदू मतों का अधिकतम ध्रूवीकरण है; ममता की रणनीति हिंदू पहचान को बंगाली अस्मिता के साथ समाहित कर अल्पसंख्यकों के विश्वास को बनाए रखना है। मुस्लिम दलों की सक्रियता तृणमूल के लिए चुनौती है, पर वह भाजपा के लिए अवसर भी है। यह त्रिकोणीय-संभावना चुनाव को जटिल बनाती है। परंतु अंतत: लोकतंत्र की परिपक्वता मतदाता तय करता है। यदि बंगाल का मतदाता विकास, रोजगार और सुशासन को प्राथमिकता देता है, तो राजनीतिक दलों को अपना विमर्श बदलना होगा। यदि वह पहचान की राजनीति को स्वीकार करता है, तो वही भविष्य की दिशा बनेगी। प्रश्न केवल यह नहीं कि कौन जीतेगा; प्रश्न यह है कि जीत का एजेंडा क्या होगा?

क्या धर्म के आधार पर लड़ा गया चुनाव सार्थक मूल्य स्थापित कर पाएगा? या यह राज्य को और अधिक वैचारिक खाइयों में धकेल देगा? बंगाल की धरती ने अनेक बार भारत को नई वैचारिक दिशा दी है। आज फिर अवसर है-या तो वह धर्म बनाम धर्म की बहस में उलझे, या धर्म को नैतिकता और विकास की प्रेरणा बनाकर नई राजनीति की राह खोले। चुनाव परिणाम चाहे जो हो, असली कसौटी यही होगी कि क्या बंगाल अपनी आर्थिक ऊर्जा, सांस्कृतिक उदारता और सामाजिक समरसता को पुन: प्राप्त कर पाता है। यदि नहीं, तो धर्म की ध्वजा चाहे जितनी ऊंची फहराई जाए, विकास का शून्य अंतत: सबको दिखाई देगा।

पाकिस्तान का आतंक पर दोहरी नीति वैश्विक मंच पर दावों की खुली पोल

देवेश त्रिपाठी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नवीनतम रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को पिछले वर्ष नवंबर में दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक हमले से जोड़ा गया है, ने एक बार फिर पाकिस्तान की पाखंडपूर्ण नीति को बेनकाब किया है। गौरतलब है कि इस हादसे में धीमी गति से चल रही एक कार में हुए भीषण विस्फोट से 15 निर्दोष मारे गए थे और दर्जनों घायल हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार, एक सदस्य देश ने जानकारी दी है कि जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जो साबित करता है कि यह आतंकी संगठन अब भी पूरी तरह से सक्रिय है। इससे पाकिस्तान के उन दावों की पोल भी खुलती है, जिनमें वह जैश जैसे आतंकी संगठनों के पूरी तरह से खत्म होने की डींगे हांकता रहा है। रिपोर्ट यह खुलासा भी करती है कि जैश प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने पिछले वर्ष अक्तूबर में ही अपनी महिला विंग जमात-उल-मुमिनात भी बनाई थी। रिपोर्ट में सदस्य देशों के बीच जैश की स्थिति की लेकर विरोधाभास दिखता है, लेकिन इससे साफ संकेत मिलता है कि यह आतंकी संगठन न केवल सक्रिय है, बल्कि अपने नेटवर्क के विस्तार की योजना भी बना रहा है। दरअसल, पाकिस्तान का पाखंड लंबे समय से जगजाहिर है। वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पर खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है, पर हकीकत कुछ और ही है। इससे पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची से बाहर किए जाने पर भी सवाल उठते हैं। कनाडा स्थित जियोपॉलिटिकल मॉनिटर की हालिया रिपोर्ट भी कहती है कि पाकिस्तान को इस सूची से हटाना समय से पहले लिया गया निर्णय था, क्योंकि देश में आतंकी गतिविधियां और इनके लिए फंडिंग लगातार जारी है। पाकिस्तान को सिर्फ जैश ही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के मामले में भी तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि बीएलए को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट में पहलगाम हमले का भी जिक्र है, जिसे द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने अंजाम दिया था, जो लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है। यह तथ्य ही है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की संरचना, विचारधारा, प्रशिक्षण और फंडिंग के स्रोत भी समान हैं, बस अंतरराष्ट्रीय निगरानी से बचने के लिए नाम बदले गए हैं। लिहाजा, यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चेतावनी है कि अगर पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं बनाया गया, तो यहां आतंकवाद की जड़ें और गहरी होंगी।

भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा एआई कैपिटल?

सनत जैन

भारत की राजधानी दिल्ली में सोमवार को दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट का आयोजन शुरु हो गया है। यह आयोजन 5 दिन तक चलेगा। इस समिट में शामिल होने के लिए दुनिया भर के 100 से अधिक कंपनियों के सीईओ, 20 राष्ट्राध्यक्ष तथा 135 देश के डेलिकेट शामिल हो रहे हैं। इस समिट में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार तीन लाख से अधिक लोगों ने समिट में आने के लिए पंजीयन कराया है। एआई का उपयोग बड़े पैमाने पर हेल्थ, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में होने जा रहा है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में भी एआई तकनीकी पर आधारित रोबोट इत्यादि भी बड़े पैमाने पर अगले कुछ वर्षों में देखने को मिलेंगे। एआई तकनीकी के माध्यम से दुनिया एक नए बदलाव की दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इसके परिणाम अच्छे होंगे, या बुरे यह कहना मुश्किल है। जिस तरह से 1993 में वैश्विक व्यापार संधि के माध्यम से सारी दुनिया में एक आर्थिक क्रांति की लहर पैदा की गई थी। कर्ज लेकर विकास करने और खर्च करने की नई प्रवृत्ति दुनिया के देशों और उनके नागरिकों के बीच में फैलाई गई। एक नये बाजारबाद की परिकल्पना को साकार किया गया। दुनिया के सभी देशों ने कर्ज लिया विकास की दौड़ में शामिल हो गए। वहीं आम नागरिकों को भी बैंकों और एनएफसी कंपनियों के माध्यम से कर्ज देकर उन्हें बाजारबाद की ओर धकेला गया। आज उसके दुष्परिणाम सारी दुनिया के देशों में देखने को मिल रहे हैं। सभी देशों की सरकारें भारी कर्ज से लदी हुई हैं। संस्थाओं के ऊपर भी भारी कर्ज हैं। इसी तरीके से दुनियाभर के आम नागरिक भी कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। ब्याज और किस्त का बोझ लगातार बढ़ता चला गया। विकास की जो परिकल्पना की गई थी, उसमें अब कुठाराघात होना शुरू हो गया है। सारा विश्व उधार की अर्थव्यवस्था को लेकर संकट में आ गया है। महंगाई और बेरोजगारी के कारण आम आदमी का जीवन दूभर हो गया

है। इसी दौर में एआई और डिजिटल तकनीकी के माध्यम से जो नए-नए प्रयोग किये जा रहे हैं, इसके सुखद परिणाम या दुष्परिणाम होंगे, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। दुनिया के सभी देशों में एआई को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्लासरूम स्मार्ट होंगे, यहां पर शिक्षकों की जरूरत नहीं होगी। स्मार्ट क्लासों में डिजिटल उपकरण और एआई की सहायता से स्कूलों और कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में जिन कामों के लिए भारी संख्या में मजदूरों को लगाया जाता था, उस काम को अब बहुत कम समय में डिजिटल और एआई तकनीकी की मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। रही सही कसर सर्विस क्षेत्र में जिस तरह से रोबोट, अब मानवों का स्थान लेते चले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब यह तकनीकी अपने शबाब पर होगी, तो लोगों को कैसे रोजगार या मजदूरी से जोड़ा जा सकेगा, इसको लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है।

अभी एआई तकनीकी का आगमन पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसके बाद भी भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोगों के ऊपर कर्ज है, उनकी क्रय शक्ति लगातार घटती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें रोजगार भी नहीं मिलेगा, तो सामाजिक व्यवस्था को कैसे नियंत्रित किया जा सकेगा। इस पर कोई चर्चा कहीं पर भी नहीं हो रही है। सभी जगह एआई से जुड़ी तकनीकि के माध्यम से कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ाने की बात की जा रही है। सभी क्षेत्रों को तकनीकी से जोड़ा जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में जहां पर बड़े पैमाने पर मानव संसाधन का उपयोग होता है। सर्विस के क्षेत्र में भारत सहित दुनियाभर के करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता था। अब उन सारे कामों के लिए एआई तकनीकी डिजिटल मशीनी उपकरणों द्वारा काम कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो मानव प्रजाति होगी, उसका गुजारा किस तरह से होगा, इस विषय पर दुनिया के किसी भी देश में कोई चर्चा नहीं हो रही है। 1993 में वैश्विक व्यापार संधि के तहत उधार की आर्थिक व्यवस्था का जो खेल विश्वव्यापी खेला गया था, उसमें अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए। इसका लाभ गिने चुने पूंजीपतियों को मिला। जिसके कारण दुनिया के सभी देश वर्तमान में महंगाई बेरोजगारी और अन्य समस्याओं के कारण अपनी ही जनता के साथ लड़ते हुए दिख रहे हैं। अब एआई का जो नया शिगुफा आया है वह दुनिया की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में किस तरह का असर डालेगा, इसकी चिंता किसी को नहीं है। लगता है कि हम एक बार फिर आदम युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर अपने अलावा और किसी के अस्तित्व की नहीं सोचते हैं। सामाजिक एवं मानवीय विकास के लिए अब हमारी कोई प्रतिबद्धता और नैतिकता नहीं बची है। आर्थिक और भौतिक संसाधनों ने हमें मशीनों की तरह असंवेदनशील बना दिया है। समय के साथ परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन के साथ समन्वय बनाए रखना जरूरी होता है। जिस तरह से एआई को लेकर बिना सोचे-समझे सारी दुनिया आगे बढ़ रही हैं, इस दिशा में चिंतन की जरूरत है। भारत के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिये। यदि हम एआई तकनीकी के पीछे भागकर अन्य कारणों को उपेक्षित करेंगे, तो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। भारत सरकार को इस दिशा में विचार-विमर्श करने के बाद ही निर्णय लेने की जरूरत है। सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में एआई का उतना ही उपयोग किया जाना चाहिए, जो देश के लिए वर्तमान संदर्भ में जरूरी हो।

न संघर्ष थमेगा न होगा हसीना का प्रत्यर्पण

उमेश चतुर्वेदी

बांग्लादेश में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की भारी जीत के बाद लंदन की जगह दिल्ली ने ले ली है। जब शेख हसीना ढाका से सरकार चलाती थीं, तब तारिक लंदन से उस पर निगाह रखते थे। अब रहमान सरकार चलायेंगे और हसीना दिल्ली से उस पर निगाह रखेंगी. उसका मतलब यह नहीं है कि रहमान हसीना के प्रत्यर्पण की माँग नहीं करेंगे। हसीना के प्रत्यर्पण की माँग कार्यवाहक सरकार के मुखिया मो. यूनुस भी करते रहे हैं और तारिक भी करते रहेंगे। बांग्लादेश में विद्रोह के बाद शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। इस बहाने उनके प्रत्यर्पण की माँग तारिक समेत कई अन्य नेता भी करते रहे हैं। लेकिन अब तारिक का सुर नरम हो सकता है। इसकी वजह यह है कि वे यूनुस की तुलना में कहीं ज्यादा वैध लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया बनने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक सत्ता उतनी कट्टर और कठोर नहीं हो सकती, जैसी वीणा वैध मतदान के बाद आईं सरकारें होतीं हैं। वैसे भी भारत शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजने जा रहा है।

बीएनपी का रूख भारत समर्थक तो नहीं ही रहा है, लेकिन बीएनपी प्रमुख ख़ालिदा जिया के निधन के बाद भारत ने जिस तरह का रुख़ अपनाया, उससे तारिक के मन की गाँठ खुली है। ख़ालिदा के शोक के वक़्त जिस तरह भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कदम उठाया और ढाका जाकर तारिक से दुख व्यक्त किया, उसे बांग्लादेश के साथ भारत की भावी रणनीति और संभावनाशील संबंधों की बानगी माना जा सकता है। भारत को अंदेशा था कि चुनावों में बीएनपी को समर्थन मिल सकता है। इसलिए उसने सही समय पर सही कदम उठाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। वैसे भी बांग्लादेश की सबसे प्रभावी पार्टी रही अवामी लीग ने चुनावों का बहिष्कार करने की घोषणा कर रखी थी। फिर यूनुस सरकार और कट्टरपंथी जमात ए इस्लाम के नेताओं ने अवामी लीग की राह में जमकर कांटे बोए। ऐसे में बीएनपी की जीत की उम्मीद बेमानी भी नहीं थी।

खालिदा जिया के निधन के बाद हुई एस जयशंकर की ढाका यात्रा से ही भारत की ओर से तारिक रहमान से संपर्क साधना शुरू हो गया था। इसका असर तारिक के चुनाव प्रचार में भी दिखाई दिया। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भूलकर भी भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जिससे भविष्य में दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों की उम्मीद जगी है। हसीना की वापसी पर भारत कहता रहा है कि शेख़ हसीना को बांग्लादेश लौटना है या नहीं, इसका फैसला उन्हें ही करना है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर कह चुके हैं कि हसीना 'खास परिस्थितियों' में भारत आई थीं और वह स्थिति उनके भविष्य को तय करने में बड़ा रोल निभाएगी। कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने तारिक रहमान को जीत की बधाई दी है। चुनाव आयोग के आधिकारिक नतीजों से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी की जीत को जनता का भरोसा बताने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के साथ काम करने को तैयार है।

चुनाव जीतने के बावजूद बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री तारिक की चुनौतियां कम नहीं होने जा रहीं हैं। इसकी वजह है, बांग्लादेश के बीते चुनाव में बेहद कम मतदान। जिसमें सिर्फ 48 प्रतिशत वोटिंग हुई है, यानि 52 प्रतिशत लोगो ने मतदान ही नहीं किया। ध्यान देने की बात है कि शेख हसीना को बांग्लादेश के 35 से प्रतिशत लोगों का समर्थन मिलता रहा है। कम मतदान का मतलब है कि हसीना के समर्थकों ने बड़े पैमाने पर चुनाव का बहिष्कार किया। इसके साथ ही केवल 48 प्रतिशत मतदान का मतलब है कि तारिक रहमान की अगुआई वाले गठबंधन को देश के ज्यादतर लोगों का समर्थन नहीं मिला। गौर करने की बात है कि बीएनपी की अगुआई वाले गठबंधन में पार्टी जमात-ए-इस्लामी, छात्रों की पार्टी एनसीए और जातीय पार्टी शामिल हैं। इसका अर्थ यह है कि बीते चुनाव में बीएनपी को 25 से प्रतिशत मत ही मिले और इतने कम वोट से ही वह सत्ता संभालने जा रही है। इसका संदेश साफ़ है कि हसीना का वोट बैंक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वह फिलहाल चुप है। इससे अवामी लीग के लिए भविष्य में वापसी की उम्मीद तो बनती ही है, बीएनपी के लिए चेतावनी भी है।

आधे से भी कम मतदान के बाद मिली जीत भी वैध नहीं मानी जा सकती। अवामी लीग के ख़िलाफ़ बगावत के बीज उनके आख़िरी चुनाव के दौरान तत्कालीन विपक्षी दलों के चुनाव बहिष्कार से ही पड़ गए थे। कुछ वैसा ही हाल बीएनपी के साथ भी हो सकता है। आधे से भी कम आबादी की वोटिंग आगे जाकर जीतने वाली सरकार की वैधता पर सवाल का कारण बन सकती है। शेख हसीना भी जानती हैं कि हिंसक प्रदर्शन के बाद हुए चुनाव के बाद आई नई सरकार को करीब तीस प्रतिशत लोगों का ही समर्थन हासिल है। कम मतदान और मौजूदा सरकार का कम आधार आगे चलकर शेख हसीना के लिए संघर्ष का नया बहाना बन सकता है। वे इसे अपने लिए नैतिक जीत बता सकतीं हैं और इस आधार पर अवामी लीग के लिए फिर से सहयोग की व्यापक माँग कर सकती हैं। वैसे भी वे पहले यूनुस सरकार के ख़िलाफ़ लोगों से उठ खड़े होने की अपील कर चुकी हैं। साफ़ है कि बांग्लादेश का न तो संघर्ष ख़त्म होने जा रहा है और न शेख हसीना का प्रत्यर्पण. इस हालात में भारत को संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ना होगा।

रहमान के नेतृत्व वाले बांग्लादेश से खासी उम्मीदें

डॉ हिदायत अहमद खान

बांग्लादेश के आम चुनाव परिणामों ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने के लिए एक कोरी डायरी पेश कर दी है। इसमें नई सरकार के काम-काज के साथ ही उनके असर को बिंदुवार रेखांकित किया जा सकेगा। दरअसल तारिक रहमान की 17 वर्ष बाद स्वदेश वापसी और उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की निर्णायक जीत ने सत्ता संतुलन बदल दिया है। यह चुनाव जुलाई 2024 की हिंसक उथल-पुथल और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लंबे शासन के अंत के बाद हुआ। स्वाभाविक है कि अब सबकी नजर नई सरकार की कथनी और करनी के साथ ही साथ विदेश नीति पर है। सवाल यही कि क्या ढाका नई दिल्ली के करीब आएगा या बीजिंग और इस्लामाबाद की ओर झुकेगा? वैसे भी भारत के लिए यह सवाल केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व का है। याद करें जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के दमन के खिलाफ मुक्ति संग्राम छिड़ा, तब भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई। भारतीय सेना के हस्तक्षेप, शरणार्थियों को आश्रय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समर्थन ने स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए भारत-बांग्लादेश संबंध केवल पड़ोसी देशों का रिश्ता नहीं, बल्कि साझा इतिहास, बलिदान और सांस्कृतिक निकटता से जुड़ा है। आखिर यह कौन नहीं जानता कि तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दृढ़ कूटनीतिक और सैन्य रणनीति ने पाकिस्तान को 13 दिनों के युद्ध में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वक्त बदला और हालात भी बदले लेकिन भारत ने कभी भी बांग्लादेश के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव कभी नहीं किया। हर समय कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने का काम किया, आर्थिक मदद प्रदान करने से भी पीछे नहीं हटा। यही वजह रही कि जैसे ही बीएनपी की बंपर जीत सामने आई नई दिल्ली ने तेजी से पहल करते हुए बधाई संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक, समावेशी और प्रगतिशील बांग्लादेश की कामना की। यह संदेश औपचारिक जरूर था, लेकिन इसके निहितार्थ स्पष्ट थे, भारत पिछले डेढ़ वर्ष की अस्थिरता, चीन-पाकिस्तान की बढ़ती सक्रियता और अल्पसंख्यकों पर हमलों जैसी चिंताओं को पीछे छोड़ स्थिर संबंध चाहता है। गौरतलब है कि बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। वे पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। निर्वासन के लंबे काल के बाद उनकी वापसी ने जनता में उत्साह पैदा किया है। चुनाव प्रचार के दौरान उनका मेरे पास बांग्लादेश के लिए एक योजना है वाला संदेश नई शुरुआत का संकेत था। उन्होंने यह भी कहा है कि वे भारत के हितों का सम्मान करेंगे, यह बयान उनकी मां की बांग्लादेश पहले नीति से थोड़ा संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण दर्शाता है। बावजूद इसके बांग्लादेश को लेकर भारत की चिंताएं तीन आयामों में केंद्रित हैं। पहला, कहीं पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश का कोई त्रिकोणीय समीकरण न उभर आए। दूसरा, सीमा और आंतरिक सुरक्षा, विशेषकर अवैध घुसपैठ और पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता। तीसरा, आर्थिक हित। भारत को बांग्लादेश के साथ व्यापार में उल्लेखनीय लाभ है; वह वहां के वस्त्र उद्योग को बड़े पैमाने पर कच्चा कपास निर्यात करता है। स्थिर संबंध दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभकारी होंगे। शेख हसीना के काल में संबंध अपेक्षाकृत स्थिर रहे। सीमा समझौते, यातायात संपर्क और सुरक्षा सहयोग में प्रगति हुई। हालांकि अवामी लीग इस बार चुनावी मैदान से बाहर रही और हसीना पर कानूनी संकट भी मंडरा रहा है, लेकिन यह भी सच है कि सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत को बदलती राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाना ही होगा। एक सकारात्मक संकेत यह है कि कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी सरकार का हिस्सा नहीं बन रही। यदि ऐसा होता तो भारत की सुरक्षा चिंताएं और गहरी हो सकती थीं। चीन की बढ़ती आर्थिक मौजूदगी, विशेषकर बंदरगाह और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय है।

अधिक वजन की महिलाओं को फायब्रॉइड का खतरा

अधिक वजन वाली महिलाओं को फायब्रॉइड (गांठ) का खतरा बना रहता है। शुरुआत में रोग के लक्षण नहीं दिखते। मुख्य रूप से लक्षण फायब्रॉइड के आकार, संख्या या वह गर्भाशय की किस दीवार पर है इसपर निर्भर करता है। गर्भाशय की मांसपेशियों में वृद्धि होकर गांठ का रूप ले लेना यूट्रस फायब्रॉइड की समस्या है। ज्यादातर मामलों में ये गांठें कैंसर की नहीं होती हैं पर कुछ मामलों में ये कैंसर में बदल सकती हैं। सोनोग्राफी से गांठ के आकार व जगह का पता चलता हैं।

जगह के अनुसार माहवारी अधिक या इस दौरान रक्त के ज्यादा थक्के निकलना जैसे समस्या होती है। खून की कमी से थकान व कमजोरी रहती है। यूरिन संबंधी परेशानी भी हो सकती है।

हार्मोन्स में गड़बड़ी फायब्रॉइड की मुख्य वजह है। विशेषकर अधिक वजन, अधिक उम्र, गर्भनिरोधक दवाएं लेने व गर्भवती महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा स्त्रावित होने से फायब्रॉइड बनने लगाता है। गंभीर स्थिति में किडनी में सूजन आ जाती है।

40 से अधिक उम्र की जो महिलाएं बच्चा चाहती हैं उनमें इस गांठ को निकाल देते हैं। वहीं, अधिक उम्र में यूट्रस को पूरी तरह से बाहर निकालना एक विकल्प है। आयुर्वेद में लक्षणों के साथ गांठ के आकार को बढने से रोकने पर इलाज होता है। इसके लिए रोगी को जौ का दलिया, सत्तू व रोटी, शाली चावल घी संग खीर बनाकर, गुलाब की पंखुडियां या धागामिश्री खाने को देते हैं। शोधन चिकित्सा में वमन, विरेचन कराते हैं। इमरजेंसी में जब महिला को सामान्य से अधिक ब्लीडिंग हो तो हेमामिलिस, कार्बोनेज दवा अन्य लक्षण, रोगी की स्थिति व गांठ की जगह देखकर देते हैं।

गर्भधारण के अलावा जिनकी फैलोपियन ट्यूब के नजदीक, ग्रीवा के मुंह पर यदि फायब्रॉइड हैं तो इंफर्टिलिटी का खतरा रहता है। गर्भावस्था के साथ यदि फायब्रॉइड हों तो गर्भपात होने की आशंका रहती है। गर्भावस्था के दौरान ये फायब्रॉइड शिशु की सामान्य पोजिशन को भी बदल देती हैं। लंबे समय तक नजरअंदाज करने पर तेज दर्द हो सकता है और महिला कोमा में जा सकती है।

घरेलू उपायों से हमारी सुंदरता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं

खूबसूरती बढ़ाने के लिए महिलाएं आजकल तरह तरह के उपाय करती हैं और महंगे सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करती हैं पर क्या आप जानती हैं खूबसूरती का खजाना आपके रसोईघर में ही उपलब्ध है। आपके घर में ऐसे कई खाद्य पदार्थ मौजूद होते हैं, जो हमारी सुंदरता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

प्रतिदिन चेहरे पर रुई के फाहे से कच्चा दूध लगाने पर चेहरे पर मौजूद ध्ब्बे हल्के हो जाते हैं। बाद में चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें ।आलू का रस निकालकर त्वचा पर लगाने से दाग-धब्बों से राहत मिलती है। आलू में मौजूद पोटैशियम सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम त्वचा की सफाई में मदद करता है।

कच्चे आलू को काटकर आंखों के नीचे प्रतिदिन थोड़ी देर मलने से आंखों के नीचे का

कालापन दूर होता है और त्वचा की रंगत भी निखरती है ।शोधों से पता चला है कि आलू का रस बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, जिससे बालों में मौजूद अतिरिक्त तेल साफ हो जाता है। यही नहीं कच्चे आलू के रस से बालों को धोने पर बाल मजबूत होते हैं।

संतरा : चेहरे पर प्रतिदिन संतरे का ताजा रस लगाने से निखार आता है।

संतरे के छिलकों को थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से मुहांसों की समस्या दूर होती है। अगर आपकी त्वचा रूखी है तो संतरा एक बेहतरीन मॉइश्चराइजर का काम करता है। एक चम्मच संतरे के रस में आधा चम्मच शहद और एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगाकर करीब 15 मिनट के लिए छोड़ दें। बाद में साफ करें।

एक सेब लेकर उसे अच्छी तरह मसल लें। इसे चेहरे पर फेसपैक की तरह लगाएं। इससे त्वचा में निखार आता है। साथ ही कसावट भी आती है। सेब की एक स्लाइस काटकर इसे दांतों पर मलने से दांतों में चमक आती है। चेहरे पर ताजा अनानास का रस लगाने से त्वचा में निखार आता है। बेहतर परिणाम के लिए इसे दिन में कई बार लगाएं।

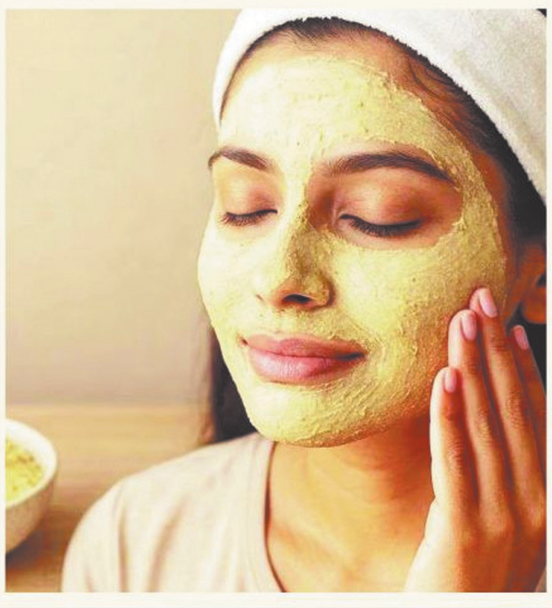

काफी कारगर हो सकता है दर्द को दूर करने के लिए घरेलु नुस्खा

काफी कारगर हो सकता है दर्द को दूर करने के लिए घरेलु नुस्खा में अधिकतर महिलाएं जोड़ों के दर्द से परेशान रहती हैं। इससे उन्हें उठने-बैठने के अलावा करवट लेने में भी तकलीफ होती है। कई बार तो तापमान कम होने के साथ ही यह जोड़ों का दर्द असहनीय भी जाता है ऐसे में कुछ घरेलु उपाय अपनाकर आप जोड़ों के दर्द से राहत पा सकती है।

जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए व्यायाम तो एक कारगर तरीका है ही दर्द को दूर करने के लिए घरेलु नुस्खा भी काफी कारगर हो सकता है। इसमें किसी प्रकार का खर्च भी नहीं लगता।

नींबू के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द से निजात पाई जा सकती है। नींबू के छिलके को घुटने पर लगाने से दर्द में काफी आराम मिलता है। नींबू में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। नींबू में मैग्नीशियम, पोटैशियम, कैल्शियम विटामिन ए, सी, बी 1 और बी6 पाया जाता है। ये सभी पोषक तत्व ही दर्द से आराम दिलाते हैं।

जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए सबसे पहले 2 नीबूं के छिलके और तकरीबन 100एमएल ऑलिव ऑयल लेना होगा। इसके बाद नींबू को किसी जॉर में डालें और फिर इसमें ऑलिव ऑयल डालिए। ऐसा करने के बाद करीब दो हफ्तों तक जॉर को बंद करके रख दें। 2 हफ्तों के बाद इस मिश्रण को रेशमी कपड़े में लेकर रात को दर्द की जगह लगाकर उसे बैंडेज से ढंककर छोड़ दें। ऐसा करने से धीरे-धीरे पुराने से पुराना दर्द भी दूर हो जाएगा।

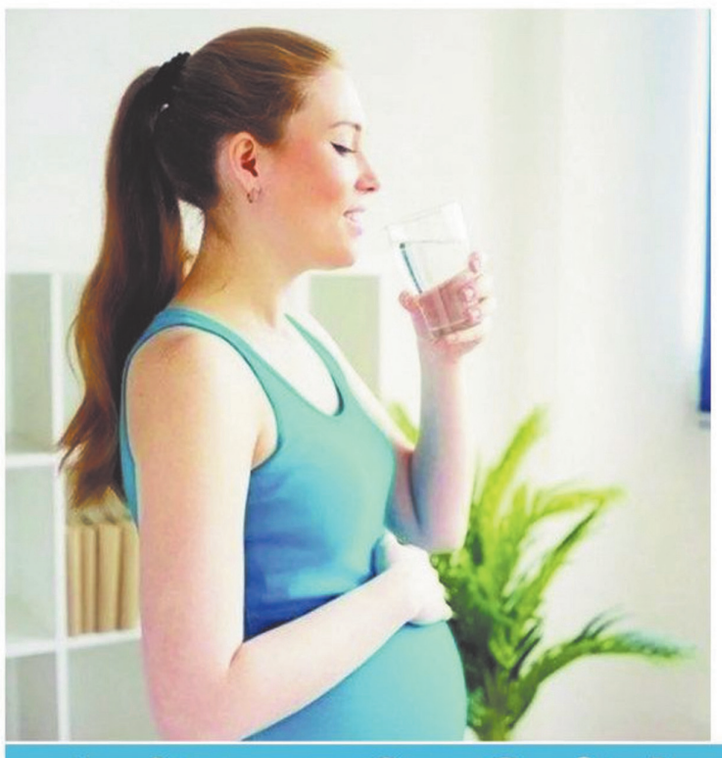

गर्भावस्था में बढ़े वजन को इस प्रकार करें कम

गर्भावस्था के बाद महिलाओं में वजन बढ़ बढ़ना एक आम समस्या है जिसे ठीक करने व्यायाम के साथ ही खानपान का भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसाले भी उपयोगी रहते हैं। खासकर जीरे वाला पानी विशेष रुप से लाभदायक रहेगा।

जीरे वाला पानी शरीर के कॉलेस्ट्रॉल और बीपी को ठीक करता है। इससे दिल की बीमारी का खतरा भी कम होता है।

शरीर में ग्लूकोज का स्तर ठीक रहता है, डायबिटीज का खतरा भी कम होता है।

डिलीवरी के बाद जीरे वाला पानी वजन घटाने में मददगार साबित होता है।

यह भी माना जाता है कि गर्भावस्था के बाद जीरा पानी पीने से दूध न बनने की समस्या भी ठीक होती है।इस पानी से दूध बनने लगता है।

जीरा पानी से रक्त संचार ठीक होता है। शरीर में समान रूप से रक्त का संचार होता है, जिससे मांसपेशियों के विकास में भी मदद मिलती है। मांसपेशियों में लगी चोट भी इससे ठीक होती है।

जीरा पानी पीने से मेटाबोलिज्म ठीक होता है। इसकी वजह से वजन नहीं बढ़ता।

यह खून की कमी अनीमिया से भी बचाता है।

बुखार कम करने में भी जीरे का पानी सहायक है। इसे पीने से छोटा-मोटा बुखार तो ऐसे ही उतर जाता है।

जीरा पानी पीने से नींद अच्छी आती है। इसलिए अगर आपको नींद न आने की समस्या है तो रोजाना जीरे वाला पानी पीने की आदत डालें।

ठंड में इन 5 बीमारियों से रहें सावधान

नहीं तो लापरवाही पड़ सकती है भारी

फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन उत्तर भारत में सर्दी का असर अभी भी बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी के चलते मैदानी राज्यों में तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। कई इलाकों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इस बदलते मौसम को लेकर डॉक्टरों ने चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक बढ़ती ठंड कुछ खास बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी सेहत को बिगाड़ सकती है।

दिल के मरीजों पर सबसे ज्यादा खतरा

डॉक्टरों के मुताबिक, सर्दी का सबसे ज्यादा असर दिल के मरीजों पर पड़ता है।

ठंड में ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट अटैक का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है।

सुबह-सुबह ठंडी हवा में टहलने से बचें

नियमित दवाइयों में कोई लापरवाही न करें

शरीर को पूरी तरह गर्म रखें

सीने में दर्द, सांस फूलना या अत्यधिक थकान महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

अस्थमा और सांस की बीमारी वालों को सतर्क रहने की जरूरत

ठंड बढ़ने के साथ अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है।

ठंडी हवा के कारण सांस लेने में दिक्कत, खांसी और घरघराहट जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं।

बाहर निकलते समय मास्क पहनें

ठंडी चीजों के सेवन से बचें

डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं और इनहेलर नियमित रूप से लें

रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।

डायबिटीज मरीजों का बिगड़ सकता है शुगर लेवल

सर्दी के मौसम में शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, जिसका सीधा असर ब्लड शुगर लेवल पर पड़ता है।

इसके अलावा हाथ-पैरों में सुन्नता और घावों के देर से भरने की समस्या भी बढ़ सकती है।

नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करें

संतुलित और पौष्टिक आहार लें

रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें।

जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस के मरीजों को परेशानी

ठंड के कारण जोड़ों में जकड़न और दर्द की समस्या आम हो जाती है।

खासकर बुजुर्गों और आर्थराइटिस के मरीजों को अधिक दिक्कत होती है।

गर्म कपड़े पहनें

हल्की स्ट्रेचिंग और योग को दिनचर्या में शामिल करें

लंबे समय तक ठंडी जगह पर बैठने से बचें।

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खतरे की घंटी

डॉक्टरों के अनुसार, सर्दी में शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए ब्लड फ्लो में बदलाव होता है।

जिससे बीपी अचानक बढ़ सकता है।

ज्यादा ठंड में बाहर निकलने से बचें

नमक का सेवन सीमित रखें

तनाव से दूरी बनाएं

नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक करते रहें।

डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी के मौसम में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।सही दिनचर्या, समय पर दवाइयां और मौसम के अनुसार सावधानी बरतकर इन बीमारियों से होने वाले खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

हमारी त्वचा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण यानि (स्मॉग) सिर्फ सेहत को ही नहीं बल्कि त्वचा को भी काफी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में त्वचा को खास ख्याल की जरूरत होती है। त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण हमारी त्वचा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।

दरअसल, हवा में मौजूद धूल हमारी त्वचा की कोशिकाओं मे ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है। त्वचा में ऑक्सीजन की कमी के कारण समय से पहले ही झुर्रियां पड़ जाती हैं। साथ ही यह धूल में मौजूद फ्री रेडिकल्स त्वचा को पूरी तरह से नष्ट करने के साथ ही कोलेजन को बनने से रोकता है।

प्रदूषण से सिर्फ झुर्रियां ही नहीं बल्कि त्वचा रुखी भी पड़ जाती है। त्वचा पर एलर्जी की वजह से जगह-जगह लाल धब्बे पड़ जाते हैं और कील मुहांसे भी काफी ज्यादा निकलने लगते हैं पर कुछ सावधानी रखकर आप अपनी त्वचा को को खराब होने से बचा सकती हैं।

प्रतिदिन हर 4 घंटे बाद अपने स्किन पर क्लींजर और टोनर लगाएं।

यूवी रेज से अपनी स्किन को बचाने और तरोताजा रखने के लिए रोजाना सन स्क्रिन जरूर लगाएं।

जीवाणुओं से होने वाले संक्रमण से बचने के लिए अपने हाथों पर हमेशा सेनिटाइजर लगाएं।

अपने चेहरे को बार बार हाथ न लगायें क्योंकि ऐसा करने से आपके हाथों के जीवाणु आपके चेहरे की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

हवा में मौजूद धूल आपकी त्वचा के रोम छिद्र को बंद कर देती है, जिससे त्वचा सांस नहीं ले पाती। इससे आपकी त्वचा में ब्लैक हेड्स और कील मुहांसे निकल आते हैं। इसलिए सप्ताह में 2 बार स्क्रब का इस्तेमाल जरूर करें, खासकर जिनकी तैलीय त्वचा है।

दिन में तकरीबन 4 लीटर तक पानी पिएं। घर से बाहर निकलते वक्त भी पानी पिएं। इससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई सही बनी रहेगी और वातावरण में मौजूद जहरीली गैसें अगर ब्लड तक पहुंच भी जाएंगी तो कम नुकसान पहुंचाएंगी।

ऐसे जहरीले स्मॉग में बाहर जाना सबकी मजबूरी होती है लेकिन बाहर से आने के बाद अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से जरूर धोएं।

नहाने के बाद हल्के हाथों से तौलिए का इस्तेमाल करें। संभव हो तो नहाने के तुरंत बाद नारियल के तेल से या किसी ऑयली बॉडी लोशन से पूरे शरीर पर मसाज करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति का किया स्वागत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके भारत यात्रा पर आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा भारत में आपका स्वागत है! भारत आपके आने और हमारे आपसी रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का इंतजार कर रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी बातचीत से अलग-अलग सेक्टर में सहयोग और मजबूत होगा और दुनिया भर में तरक्की में मदद मिलेगी। मुंबई में और बाद में दिल्ली में मिलते हैं, मेरे प्यारे दोस्त इमैनुएल मैक्रों। गौरतलब है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रों मंगलवार को भारत यात्रा के लिए मुंबई पहुंचे। उनकी यह यात्रा 19 फरवरी तक चलेगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति और प्रथम महिला का मुंबई के हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया।

बीएनपी संसदीय दल के नेता चुने गए तारिक रहमान

ढाका। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान को 13वीं जातीय संसद में पार्टी के संसदीय दल का नेता सर्वसम्मति से चुना गया है। यह निर्णय आज दोपहर 12 बजे जातीय संसद भवन में आयोजित नव-निर्वाचित बीएनपी सांसदों की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में बीएनपी के महासचिव मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चले दमन, लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने और संसद की प्रभावहीनता के दौर के बाद पार्टी ने निष्पक्ष चुनाव के जरिए संसद में वापसी की है। उन्होंने कहा इस संसद में बहुमत के साथ हमने अपने युवा नेता तारिक रहमान को संसदीय दल का नेता चुना है। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भी जमात-ए-इस्लामी और बीएनपी के बीच शपथ ग्रहण को लेकर टकराव देखने को मिला।

नवजोत कौर का राहुल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला

चेन्नई। कांग्रेस से निष्कासित नेता नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर जमीनी हकीकतों से बेखबर होने का आरोप लगाया और 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार की भविष्यवाणी की। तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा कि गांधी समझदारी की बातें तो करते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पंजाब इकाई में कथित अनियमितताओं को उजागर करने के लिए आठ महीने का समय मांगा था, जिसमें चुनाव टिकटों की बिक्री के आरोप भी शामिल थे, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। मैं उनसे पद मांग रही हूं ताकि उन्हें बता सकूं कि पंजाब में आपकी पार्टी बर्बाद हो रही है। आपको अपने नीचे काम करने वाले लोगों को देखना चाहिए। और अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो आप इस पद के लायक नहीं हैं।

जल गया ब्लैक बॉक्स, हादसा या साजिश : संजय राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की 28 जनवरी को हुई विमान दुर्घटना को लेकर पवार परिवार के संदेह का समर्थन करते हुए विमान के जले हुए ब्लैक बॉक्स की स्थिति को रहस्यमय और बेहद गंभीर बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने कहा कि अजित पवार की फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स जल गया है, जिससे पवार परिवार के संदेह की पुष्टि हुई और सरकार द्वारा जांच के संचालन पर सवाल उठे। संजय राउत ने कहा कि रोहित पवार उसी परिवार के सदस्य हैं, वे तकनीकी मामलों को समझते हैं। अजित पवार की दुर्घटना के बारे में सामने आ रहे रहस्यमय तथ्य बेहद गंभीर हैं। ब्लैक बॉक्स जल गया है... 20 साल बाद भी ब्लैक बॉक्स मिल गया है, लेकिन अजित पवार की फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स जल गया है। यह कैसे संभव हो सकता है? अगर रोहित पवार ने यह मुद्दा उठाया है, तो यह गंभीर है, और अगर पवार परिवार इसकी जांच करना चाहता है, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए।

बढ़ती मुस्लिम आबादी पर मुख्यमंत्री सरमा चिंतित

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को राज्य में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि असम की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इसके पीछे बड़े पैमाने पर हुई अवैध घुसपैठ जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि असम में मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से अवैध रूप से आया है। उनके अनुसार, यह घुसपैठ मुख्य रूप से उस समय हुई जब राज्य और केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थीं। उन्होंने कहा कि उन सरकारों ने सीमाओं की सही तरीके से निगरानी नहीं की, जिससे राज्य की जनसांख्यिकीय संतुलन प्रभावित हुई है। सीएम सरमा ने यह भी दावा किया कि राज्य के कुछ लोग भविष्य में किसी भी संघर्ष की स्थिति में बांग्लादेश का समर्थन कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

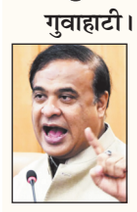

प्रधानमंत्री ने बताया शिखर सम्मेलन का उद्देश्य

जनहित और सबके फायदे के लिए हो एआई का इस्तेमाल : मोदी

नई दिल्ली। दिल्ली में आयोजित पांच दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि एआई का इस्तेमाल सभी के फायदे के लिए कैसे किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म %एक्स% पर एक पोस्ट में लिखा, %बुद्धिमत्ता, तर्कसंगतता और निर्णय लेने की क्षमता विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जनता के लिए उपयोगी बनाती है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य यह पता लगाना भी है कि एआई का उपयोग सभी के लाभ के लिए कैसे किया जा सकता है।%

16 फरवरी से शुरू हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों, मंत्रियों, वैश्विक प्रौद्योगिकी नेताओं, प्रख्यात शोधकर्ताओं, बहुपक्षीय संस्थानों और उद्योग जगत के हितधारकों को एक मंच पर लाया गया ताकि समावेशी विकास को आगे बढ़ाने, सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करने और सतत विकास को सक्षम बनाने में एआई की भूमिका पर विचार-विमर्श किया जा सके। साथ ही, यह पहली बार है कि इस मुद्दे पर इतने बड़े पैमाने पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन ग्लोबल साउथ में किया जा रहा है।

पांच दिवसीय शिखर सम्मेलन जो 20 फरवरी को समाप्त होगा, इसमें 100 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और उप मंत्री शामिल हैं, साथ ही सीईओ, संस्थापक, शिक्षाविद, शोधकर्ता, सीटीओ और परोपकारी संगठनों सहित 500 से अधिक वैश्विक एआई नेता भी शामिल होंगे। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन भाषण देंगे, जो वैश्विक सहयोग की दिशा तय करेगा और समावेशी एवं जिम्मेदार एआई के लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेगा।

शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण तीन प्रमुख वैश्विक प्रभाव चुनौतियां हैं- एआई फॉर ऑल, एआई बाय हर और युवआई- जिनका समापन फाइनलिस्टों की घोषणा और ग्रैंड फिनाले शोकेस के साथ होगा। समावेशी, जिम्मेदार और विकासोन्मुखी एआई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई ये चुनौतियां राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक विकास उद्देश्यों के अनुरूप स्केलेबल, उच्च-प्रभाव वाले एआई समाधानों को गति प्रदान करने के लिए शुरू की गई थीं।

इन चुनौतियों के लिए 60 से अधिक देशों से 4650 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जो मजबूत अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को दर्शाते हैं और जिम्मेदार और स्केलेबल एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) नवाचार के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उदय को मजबूत करते हैं। कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं द्वारा किए गए एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन के बाद, तीनों श्रेणियों में शीर्ष 70 टीमों को फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। ये फाइनलिस्ट नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, निवेशकों और शिक्षाविदों के साथ जुड़ेंगे, साथ ही राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मान्यता और सहयोग प्राप्त करेंगे।

18 फरवरी को हैदराबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से एआई और उसके व्यापक प्रभावों पर एक महत्वपूर्ण अनुसंधान संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। यह संगोष्ठी शिखर सम्मेलन का प्रमुख शैक्षणिक मंच मानी जा रही है, जहां एआई से जुड़े कई आयामों पर गंभीर विमर्श होगा। इस संगोष्ठी के लिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका सहित कई देशों से लगभग 250 शोध प्रस्तुतियां प्राप्त हुई हैं, जो इस विषय पर वैश्विक रुचि और सहभागिता को दर्शाती हैं। कार्यक्रम में एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी भाग ले रहे हैं। यह विश्व स्तर पर प्रसिद्ध एआई विशेषज्ञों और अग्रणी अनुसंधान संस्थानों को एक साथ लाता है ताकि एआई-संचालित वैज्ञानिक खोज, सुरक्षा और शासन ढांचे, बुनियादी ढांचे तक समान पहुंच और ग्लोबल साउथ में अनुसंधान सहयोग पर विचार-विमर्श किया जा सके।

दुनिया-यूएन के एजेंडे में भारत का स्थायी योगदान बहुत महत्वपूर्ण

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया और संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में भारत का स्थायी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत जैसे उभरते देशों की भूमिका लगातार बढ़ रही है और यह एक सकारात्मक बड़ा ट्रेंड है।

एंटोनियो गुटेरेस के अनुसार, भारत अब संयुक्त राष्ट्र की लगभग हर बड़ी चर्चा में एक अहम नेता बन गया है। इसमें शांति-सुरक्षा, सतत विकास और मानवाधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने खास तौर पर भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान लिए गए फैसलों की तारीफ की। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लेकिन भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने भारत को धन्यवाद देते हुए कहा, करीब 5000 भारतीय सैनिक और पुलिसकर्मी यूएन शांति मिशनों में तैनात हैं। भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पूरी तरह महिला पुलिस यूनिट भेजी थी- जो यूएन इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी। यह कदम लैंगिक समानता की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण माना गया।

एंटोनियो गुटेरेस ने एक बड़ा ट्रेंड बताया- जिसमें जी7 जैसे विकसित देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सा धीरे-धीरे घट रहा है। वहीं भारत जैसे उभरते देशों का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में ज्यादा न्याय, समानता और शांति वाली दुनिया बनने की संभावना बढ़ेगी। यूएन महासचिव ने आगे कहा- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ढांचा पुराना और कुछ हद तक अनुचित है। इसमें सुधार जरूरी है ताकि दुनिया की नई वास्तविकताओं को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यूएन केवल सुरक्षा परिषद नहीं है- 193 सदस्य देशों वाली महासभा में सभी देशों की बराबर आवाज है। एंटोनियो गुटेरेस जल्द ही भारत आएंगे और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने भारत को नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक नेता भी बताया।

गौरव गोगोई से तकरार, आत्मसम्मान को ठेस!

बोराह के इस्तीफे से असम कांग्रेस संकट में

गुवाहाटी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के असम के दो दिवसीय दौरे से कुछ ही दिन पहले, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोराह के इस्तीफे से पार्टी को गहरा झटका लगा। इस घटनाक्रम ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, खासकर विधानसभा चुनावों के नजदीक होने के कारण। बोराह के अचानक लिए गए इस फैसले से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की असम इकाई में अनिश्चितता का माहौल बन गया है।

कांग्रेस के कामकाज पर बोराह की तीखी टिप्पणियां

बोराह के इस्तीफे के रूप में सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित एक पत्र में, उन्होंने पार्टी की आंतरिक गतिशीलता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के नेतृत्व शैली पर सवाल उठाया और जिसे उन्होंने हाशिए पर धकेल दिया जाना बताया, उस पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से एपीसीसी के वर्तमान अध्यक्ष गौरव गोगोई की पाकिस्तान यात्राओं को लेकर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र किया। बोराह ने कहा कि इन आरोपों पर स्पष्ट प्रतिक्रिया न मिलने के कारण पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने राज्य इकाई में खुद को दरकिनार महसूस करने का भी जिक्र किया और कहा कि संगठन के कामकाज ने उनकी गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। बोराह ने पिछले साल गोगोई द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले 2021 से 2025 तक असम कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

छह राजनीतिक प्रस्ताव, भाजपा की पहल

बोरा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि उन्हें छह अलग-अलग पार्टियों से प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि वे आगामी चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, संभवत: अपने जन्मस्थान रंगनाडी से। इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बोराह को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का खुला निमंत्रण दिया। सरमा ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि बोराह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और पुष्टि की कि दोनों नेताओं ने फोन पर बात की है। उनकी मुलाकात तय हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के दरवाजे बोराह के लिए खुले हैं और यहां तक कि उन्होंने संकेत दिया कि अगर वे दल बदलते हैं तो वे उन्हें किसी सुरक्षित सीट से समर्थन देंगे।

इस्तीफा, अटकलें और स्पष्टीकरण

सोमवार को कई तेजी से हुए घटनाक्रमों ने भ्रम को और बढ़ा दिया। सबसे पहले बोराह ने पार्टी से अपने इस्तीफे की घोषणा की। इसके तुरंत बाद, कुछ स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी से बात की और अपना इस्तीफा वापस ले लिया। हालांकि, बोराह ने बाद में इन खबरों को खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है और उन्होंने वरिष्ठ नेताओं प्रद्युत बोरदोलोई और देबब्रता सैकिया को अपने इस्तीफे पत्र की समीक्षा करने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने कहा कि अगर वे उन्हें आश्वस्त कर सकें कि उनकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा, तो वे पुनर्विचार के लिए तैयार हैं। बोराह ने कहा, मैं पूरा दिन इंतजार करूंगा, और कहा कि वे जल्द ही अंतिम निर्णय लेंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

न्यूजीलैंड के रविंद्र-फिलिप्स की आंधी में उड़ा कनाडा

चेन्नई। युवराज समरा की शानदार पारी निष्फल साबित हुई क्योंकि न्यूजीलैंड ने मंगलवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चल रहे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के 31वें मैच में कनाडा को आठ विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ, न्यूजीलैंड सुपर एट्स के लिए क्वालीफाई करने वाली छठी टीम बन गई, और कनाडा टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार के बाद दौड़ से बाहर हो गया। 174 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए, न्यूजीलैंड ने तीसरे ओवर में सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट का विकेट खो दिया। उन्होंने 10 गेंदों पर सिर्फ छह रन बनाए। उनके तुरंत बाद फिन एलन भी आउट हो गए, जिन्होंने दो चौकों और एक छक्के सहित सिर्फ आठ गेंदों पर 21 रन बनाए।

इसके बाद रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने 72 गेंदों पर 146 रनों की अटूट साझेदारी की और कीवी टीम को सिर्फ 15.1 ओवर में आठ विकेट शेष रहते लक्ष्य तक पहुँचा दिया। फिलिप्स ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 76 रन बनाए, जिसमें चार चौके और छह छक्के शामिल थे। रवींद्र ने भी 39 गेंदों में 59 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें तीन छक्के और चार चौके शामिल थे। मैच जिताने वाले प्रदर्शन के लिए फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने फील्डिंग करते हुए तीन कैच भी पकड़े। इससे पहले, 19 वर्षीय समरा ने मात्र 65 गेंदों में 110 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और छह छक्के शामिल थे। इस पारी की बदौलत कनाडा ने न्यूजीलैंड के सामने 174 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा। समरा ने टी20 विश्व कप में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज के रूप में पाकिस्तान के अहमद शहजाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहजाद ने 2014 के टी20 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाते समय 22 वर्ष की आयु के थे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 173 अंक चढ़ा निफ्टी 25715 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में मिलेजुले रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार (17 फरवरी) को हरे निशान में बंद हुए। इसी के साथ बाजार में लगातार दूसरे सेशन में बढ़त रही। इंडेक्स में भारी वजन रखने वाले आईटी स्टॉक्स में निचले स्तर पर खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। शुरूआती कारोबार में गिरने के बाद बाजार ने वापसी की और बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त में बंद हुए। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स गिरावट के साथ 83,197 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 82,987 अंक तक फिसल गया रहा। लेकिन अंत में 173.81 अंक या 0.21 प्रतिशत की बढ़त लेकर 83,450.96 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी गिरावट के साथ 25,637 पर खुला। अंत में 42.65 अंक या 0.17 प्रतिशत की बढ़त लेकर 25,725.40 पर बंद हुआ।

डिजिटल पेमेंट्स की रफ्तार तेज

नईदिल्ली। देश में डिजिटल भुगतान तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन नकदी का चलन भी मजबूत बना हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, करेंसी इन सर्कुलेशन यानी बाजार में मौजूद कुल नकदी का मूल्य लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में दर्ज हुई है जब यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नकदी की मांग बढ़ने के पीछे कई संरचनात्मक और व्यवहारिक कारण हैं। रिसर्च के अनुसार, कुछ राज्यों में जीएसटी नोटिस के बाद छोटे व्यापारियों के बीच नकद लेनदेन की ओर झुकाव बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर जुलाई 2025 में कर्नाटक के करीब 18,000 छोटे कारोबारियों को यूपीआई ट्रांजैक्शन के आधार पर जीएसटी नोटिस भेजे गए थे।

एलन मस्क का ट्रिलियन डॉलर क्लब में एंट्री की तैयारी!

वाशिंगटन। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एलन मस्क की कुल संपत्ति फरवरी 2026 में 850 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और उम्मीद है कि वो ट्रिलियन डॉलर क्लब में जल्द एंट्री करेंगे। फोर्ब्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पहली बार 800 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। मस्क की संपत्ति में हालिया तेजी की बड़ी वजह स्पेसएक्स और एक्स एआई के बीच हुई डील है। रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेसएक्स ने एक्स एआई का अधिग्रहण किया है, जिसके बाद संयुक्त कंपनी की वैल्यूएशन करीब 1.25 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है। इसमें स्पेसएक्स की वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन डॉलर और एक्स एआई की 250 अरब डॉलर बताई गई है। मस्क की इस मर्ज्ड कंपनी में करीब 43% हिस्सेदारी है।

इन्फोसिस ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक से मिलाया हाथ

नईदिल्ली। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के शेयर मंगलवार को 3 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गए। कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक बड़ी घोषणा के चलते आई। आईटी फर्म ने एआई रिसर्च और सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनी एंथ्रोपिक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान है। इस साझेदारी के तहत टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे सेक्टर के लिए एडवांस एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस तैयार किए जाएंगे। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि यह साझेदारी सबसे पहले टेलीकॉम सेक्टर में शुरू होगी। इसके तहत एक खास एंथ्रोपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसमें अलग-अलग उद्योगों की जरूरत के मुताबिक एआई एजेंट्स तैयार और लागू किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश बजट: उपभोक्ता से उत्पादक बनाती योगी सरकार की नीतियां

शरद कोहली

उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के लिहाज से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के मुताबिक पहला। अर्थ यह कि उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं का अनुपात मानकों के अनुरूप नहीं बैठता। और यहीं से शुरू होता है चुनौतियों का सिलसिला। 25 करोड़ की आबादी की हर जरूरत पूरी करना कोई आसान काम नहीं। इन परिस्थितियों में किसी भी राज्य के लिए विकास का आदर्श मॉडल क्या हो सकता है, इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है। क्या उत्तर प्रदेश की सभी जरूरतें सरकारी रेवड़ियां बांटकर पूरी की जा सकती हैं? क्या सिर्फ बजट प्रावधानों से प्रति व्यक्ति आय अपने उच्चतम स्तर तक जा सकती है? क्या सिर्फ सरकारी पैसे से विकसित व आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? जवाब है नहीं। बुनियादी ढांचे के विकास को छोड़ दें तो समाज के विभिन्न वर्गों को दी जाने वाली बजटीय सहायता सिर्फ तात्कालिक राहत देती है। यह उनकी समस्याओं का स्थायी निराकरण नहीं करती। किसी भी राज्य की जनता का आर्थिक स्तर ऊंचा करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुनियोजित नीति के तहत बजट निर्धारण आवश्यक हो जाता है और योगी सरकार ऐसा करने में सफल रही है।

राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले उसकी जमीनी वास्तविकताओं यानी प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, कौशल, तकनीक, नवाचार, बाजार, निवेश की अनुकूलता आदि का समग्र अध्ययन जरूरी है। तभी सर्वांगीण विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है। योगी सरकार ने राज्य के लिए विकास का जो मॉडल तैयार

किया है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। यह मॉडल राज्य को उपभोग से उत्पादकता की ओर ले जाता है और यही स्थायी विकास की कुंजी है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बजाय सरकार ने दीर्घकालीन रणनीति के तहत निवेश करना बेहतर समझा। निवेश अपने लोगों में, शिक्षा के उन्नयन और उसके विस्तार में, कौशल विकास में, रोजगार के अवसर पैदा करने में, बुनियादी ढांचे के विकास में, ग्रामीण व पिछड़े इलाकों को आत्मनिर्भर बनाने में और निवेशकों के लिए राज्य को आकर्षक बनाने में। ऐसा भी नहीं है कि सरकार खर्च नहीं कर रही, बजटीय सहायता नहीं दे रही। बस, अंतर केवल इतना आया है कि सरकार वहीं पैसा लगा रही है, जहां से ठोस व स्थायी परिणाम मिलना सुनिश्चित है। पिछले कई वर्षों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार इसी दिशा में कार्यरत नजर आ रही है। और, इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। फसल सुरक्षा के साथ-साथ उन्नत तकनीक मुहैया कराई गई तो किसानों की उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। सीएम युवा उद्यमी योजना ने युवाओं को स्वरोजगार के टूल्स दिए, उन्हें नौकरी करने के बजाय रोजगार देने के लायक बनने का मंच प्रदान किया। विभिन्न योजनाओं को बजटीय सहायता देकर ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है।

सरकार चाहती तो एमएसएमई सेक्टर के लिए किसी बड़ी छूट का ऐलान कर लोक-लुभावन कदम उठा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा करने के बजाय एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को आगे बढ़ाया, छोटे उद्यमियों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने में, उनकी ब्रांडिंग में और उनके लिए बाजार तलाशने में मदद की। नतीजा यह कि ओडीओपी से एमएसएमई को जबरदस्त बूस्ट मिला। आज ओडीओपी से जुड़े उद्यमी, कारीगर, विक्रेता, सभी लोगों की आय में कई गुना वृद्धि दर्ज की जा रही है। अब वे सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं हैं, जो कितने दिन काम आता? अभी प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स के माध्यम से करीब तीन करोड़ परिवारों का पालन-पोषण हो रहा है और यह एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य का निर्यात भी 84 हजार करोड़ से बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपये तक जा पहुंचा, क्या ये सब बजटीय अनुदान से संभव होता?

जनजातीय समाज के सशक्तिकरण से बनेगा समृद्ध छत्तीसगढ़: सीएम साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैकुंठपुर में तीन दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन कोरिया महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कोरिया जिलेवासियों को 156 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की ऐतिहासिक सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने 70 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 104 कार्यों का लोकार्पण तथा 85 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक के 40 कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकास कार्य केवल निर्माण परियोजनाएँ नहीं, बल्कि कोरिया जिले की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और

उज्ज्वल भविष्य के मजबूत आधार स्तंभ हैं। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ को संपन्न और समृद्ध प्रदेश के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। राज्य सरकार ने अपने अधिकांश वादों को अल्प समय में पूरा कर दिखाया है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश की जनता से किए गए विकास संबंधी वादों को भी दो वर्षों के भीतर धरातल पर उतारा गया है।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में सभी शेष संकल्प भी पूर्ण किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई थी और अब उनके निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं। उन्होंने बस्तर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षों तक नक्सलवाद से प्रभावित रहने के कारण यह क्षेत्र विकास से वंचित रहा, लेकिन डबल इंजन सरकार के प्रयासों से नक्सल उन्मूलन में अभूतपूर्व सफलता मिली है। आज बस्तर के गांव-गांव में सड़क, अस्पताल और स्कूल खुल रहे हैं तथा उजड़े हुए गांव पुनः आबाद हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर में नियद नेल्ला नार योजना प्रारंभ की गई है, जिससे विकास कार्यों को गति मिली है। मुख्यमंत्री साय ने किसानों के हित में लिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। हाल ही में खरीदे गए धान की अंतर राशि होली से पहले किसानों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी, जिसके अंतर्गत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये किसानों को मिलेंगे।

भाजपा प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारियों को मिला मार्गदर्शन

पार्टी की विचारधारा को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचना उद्देश्य: देव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित प्रकदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में आज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कर्मठ कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यशाला का उद्देश्य संगठनात्मक दक्षता बढ़ाना, संवाद स्थापित करना और पार्टी की विचारधारा को प्रत्येक मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ तक मजबूती से पहुँचाना बताया गया। कार्यशाला में बस्तर संभाग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण के माध्यम से संगठन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय और तालमेल बनाने पर जोर दिया। इसमें बूथ प्रबंधन, सदस्यता अभियान, कार्यक्रमों का संचालन और जनता से संवाद जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया।

कार्यशाला के दौरान मुख्य वक्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि सशक्त संगठन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण, संवाद और समन्वय के माध्यम से पार्टी की विचारधारा को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुँचाया जा सकता है। बस्तर क्षेत्र की धरती से संगठन सुदृढ़ीकरण का संकल्प लेने से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और दिशा मिली। इस अवसर पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे जनता के बीच सक्रिय रहें, उनके सुझावों और शिकायतों को पार्टी नेतृत्व तक पहुँचाएं और संगठनात्मक गतिविधियों में योगदान दें।

कार्यशाला का समापन संगठनात्मक मजबूती और प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी को समझने के साथ हुआ। उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने इस प्रशिक्षण से मिले ज्ञान और दिशा को अपने-अपने क्षेत्र में लागू करने का संकल्प लिया। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने इस कार्यशाला को बस्तर संभाग में संगठन सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यशालाओं से पार्टी कार्यकर्ताओं की क्षमता और समर्पण बढ़ता है और यह संगठन को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इस प्रकार, प्रशिक्षण कार्यशाला ने बस्तर संभाग के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक दृष्टि से सशक्त बनाने और पार्टी की नीतियों तथा कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के खिलाफ राज्य सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

रायपुर। राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के खिलाफ राज्य सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर और रायपुर के अधिकारी-कर्मचारियों के वेतनवृद्धि के पक्ष में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों ने अपना पक्ष रखा है। मामले की अगली सुनवाई बीस फरवरी को रखी गई हैं।

रायपुर और जगदलपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कुल 6 राजस्व जिलों में संचालित है। 6 जिलों के अंतर्गत 73 शाखाएं ,550 सहकारी समितियां और 711 धान केंद्र संचालित हैं। रायपुर जिला सहकारी बैंक प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी बैंक है। यहां के अधिकारी-कर्मचारी लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। इसके लिए पहले वह धरना प्रदर्शन कर रहे थे जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी हाईकोर्ट के डबल बेंच में कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाते हुए वेतनवृद्धि का आदेश दिया गया था जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हो रही है जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मियों की वेतन वृद्धि प्रधान पर सुनवाई करेगी।

कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 5 सालों से वेतन वृद्धि नहीं की जा रही थी। उनका कहना है कि सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेशों के कारण उन्हें देय वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ते से वंचित रखा गया है जबकि बैंक लगातार लाभ में है। यहां के कर्मचारियों का कहना है कि सहकारिता पंजीयन अपने डॉक्टर अमोलर पवनाथ कमेटी की सिफारिशों का हवाला देते हुए रायपुर और जगदलपुर जिला सहकारी बैंकों के लिए पृथक से आदेश जारी कर वेतन वृद्धि रोक दी है। जबकि अन्य जिला सहकारी बैंकों और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक के लिए अलग आदेश लागू है।

शासन के आदेश व नियमावली के अनुसार होगी हैंडओवर की कार्यवाही

रायपुर। राज्य शासन के आदेश व नियमावली के अनुसार नगर निगम द्वारा आरडीए और हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनियों के हैंडओवर की कार्यवाही की जाएगी। राज्य शासन द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 9 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस पर आगे की प्रक्रिया और कार्यवाही के लिए शासन स्तर से जारी होने वाली विस्तृत नियमावली का इंतजार है। इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी होने पर तीनों एजेंसियां संयुक्त सर्वे कर वास्तविक स्थिति का आंकलन करेंगी।रायपुर नगर निगम के नगर निवेशक ने बताया कि सर्वे में पेयजल आपूर्ति तंत्र, सीवरेज नेटवर्क, आंतरिक सड़कों, स्ट्रीट लाइट, उद्यानों और सफाई व्यवस्था की मौजूदा हालत का तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। कई कालोनियों में 15 से 20 वर्ष पुरानी पाइपलाइन, जर्जर नालियां और खराब सड़कें हैं। हैंडओवर लेने के पहले इनका सही आंकलन जरूरी है। हैंडओवर से पहले वित्तीय भार, अतिरिक्त स्टॉफ और रखरखाव की रूपरेखा तय करना निगम के लिए अत्यावश्यक है। अधिकांश कालोनियों में जलापूर्ति की पाइपलाइन डेढ़ दशक से अधिक पुरानी है, जिनकी उपयोग अवधि लगभग समाप्ति पर है।हैंडओवर के लिए शासन से आदेश व नियमावली प्राप्त होने पर कॉलोनियों की वास्तविक स्थितियों का सर्वे किया जाएगा। इसके अनुसार ही सभी कार्यवाहियां की जाएगी। अद्यतन किसी भी प्रकार का निर्देश निगम को प्राप्त नहीं हुआ है।

महादेव घाट रोड व्यापारी संघ के साथ संवाद से समाधान कार्यक्रम आयोजित

रायपुर। संवाद से समाधान कार्यक्रम के तहत महादेव घाट रोड, लाखे नगर व्यापारी संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ डीसीपी पश्चिम जोन रायपुर, श्री संदीप पटेल तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री राहुल देव शर्मा की उपस्थिति में एक विस्तृत संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सहायक पुलिस आयुक्त, पुरानी बस्ती श्री देवांश सिंह राठौर और थाना प्रभारी पुरानी बस्ती भी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक भवन, अश्विनी नगर हॉल में किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत पुलिस व्यवस्था, व्यापारी वर्ग की जिम्मेदारियां और सुव्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करना था। अधिकारियों ने व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों को कमिश्नरेट प्रणाली के अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी दी।

मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे- कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस व्यवस्था, अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। व्यापारी वर्ग की भूमिका- दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का समान या शेड निर्माण नहीं करने का निर्देश।

दुकान के सामने ठेले, गुमटी आदि न लगाने और उल्लंघन की स्थिति में नोटिस जारी करने हेतु निगम अधिकारियों को निर्देश।सुव्यवस्थित यातायात- निगम अधिकारियों को पार्किंग स्थल निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त पट्टी लगाने का निर्देश। व्यापारियों को यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश। सुरक्षा उपाय- व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर कम से कम 30 दिन तक फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

बृजमोहन की पहल से सौगात, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू

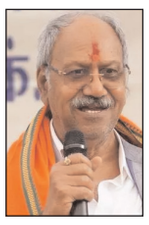

रायपुर। राजधानी के समग्र विकास और नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए मंगलवार को करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ज़मीनी कार्यों से दिखाई देता है और यही उनकी प्राथमिकता है। इस कार्यों में वामनराव लाखे वार्ड अंतर्गत प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर-3 में 48 लाख रुपये की लागत से आर.सी.सी.नाला निर्माण, मरम्मत एवं कवरिंग कार्य, गली नंबर 15 एवं मेन रोड में 21.11 लाख रुपये से नाली, पुलिया तथा सी.सी. रोड के मरम्मत एवं निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक अधोसंरचना को सशक्त बनाने की दिशा में वामनराव लाखे वार्ड स्थित शासकीय मिडिल स्कूल में 9.80 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य, शासकीय हाई स्कूल कुशालपुर में 5.95 लाख रुपये से शेड निर्माण, गायत्री प्रज्ञा मंडल मंदिर के पास करीब 10 लाख रुपये की लागत से भवन निर्माण कार्य शामिल हैं।

मालवीय रोड को किया नो-वेंडिंग और नो-पार्किंग जोन घोषित

रायपुर। व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्रों में से मालवीय रोड, जी.ई. रोड और के.के. रोड को व्यवस्थित करने की छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मुहिम रंग लाई है। चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के कुशल नेतृत्व और सतत प्रयासों के फलस्वरूप, रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला द्वारा इन प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को नो-वेंडिंग और नो-पार्किंग जोन घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ज्ञात हो कि विगत 28 जनवरी 2026 को चेम्बर भवन में श्री सतीश थौरानी की अध्यक्षता में नगर निगम और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में श्री थौरानी ने मालवीय रोड के व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए प्रशासन से मांग की थी कि फुटपाथों से अवैध कब्जा हटाया जाए और बाजार को सुव्यवस्थित करने के लिए इसे नो वेंडर जोन बनाया जाए। मालवीय रोड शारदा चैक व्यापारी संघ के अध्यक्ष एवं चेम्बर अनुशासन समिति सदस्य श्री तरल मोदी तथा संघ के महामंत्री एवं चेम्बर कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेश वासवानी ने एक औपचारिक पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को आवेदन देकर मालवीय रोड की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था और फुटपाथ पर बढ़ते अतिक्रमण के विरुद्ध नो वेंडर जोन बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाने की मांग की थी।

महन्त कॉलेज में रिदम आज

रायपुर। गांधी चौक स्थित महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम रिदम 2026 का आयोजन रविंद्र मंच कालीबाड़ी में 18 फरवरी 2026 को दोपहर 1 बजे से आयोजित है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि गृह मंत्री विजय शर्मा, विधायक पुरंदर होंगे, आयोजन में विशिष्ट अतिथि नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव उपस्थिति रहेगी वहीं आयोजन में प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय तिवारी, अनिल तिवारी, आरके गुप्ता एवं महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी विशेष आमंत्रित सदस्यों में शामिल होंगे। आयोजन के संदर्भ में जानकारी देते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी डॉ अनुपम जैन ने बताया कि आयोजन में 16 सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुत होने की सूचना छात्र-छात्राओं के ग्रुप के द्वारा दी गई है। आयोजन में सैफ और सोहेल संगीत ग्रुप शामिल होगा। आयोजन के दौरान सभी छात्र-छात्राओं को कॉलेज की निर्धारित परिधान में परिचय पत्र के साथ उपस्थित होना अनिवार्य रखा गया है। बिना परिचय धारक छात्र-छात्राओं को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं रहेगी। महाविद्यालय के 2000 से भी अधिक छात्र-छात्राएं की उपस्थिति होंगे।

भाजपा जोन अध्यक्ष की गुंडागर्दी, पीड़ित से पैसे की मांगे: वर्मा

रायपुर। रायपुर नगर निगम जोन 8 के जोन अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर की गुंडागर्दी के वॉयरल वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सत्ता के अहंकार में भाजपाई जनप्रतिनिधि जनता पर ही बर्बरता पर उतर आए हैं, इस सरकार में प्रशासन नहीं वसूली गिरोह चल रहा है, सत्ता में बैठे लोग मारपीट, गाली गलौज और गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। विधि द्वारा तय प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि इस तरह से कानून को हाथ में ले, किसी को सजा दे, सार्वजनिक तौर पर अपमानित करे। सुशासन का दावा करने वाले भाजपाई जंगल राज चला रहे हैं, कथित ट्रिपल इंजन सरकार में पीड़ित ही प्रताड़ित हो रहे हैं और जिन पर जनता की सुविधा और सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही अत्याचारी बन गए हैं।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि किसी भी स्थानीय निकाय क्षेत्र में गैर अनुमति प्राप्त निर्माण के नियमितीकरण की निर्धारित प्रक्रिया अधिनियमित है। यदि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही करनी है तो उसकी भी प्रक्रिया तय है, पीड़ित का दावा है कि उन्होंने तय प्रक्रिया के तहत आवेदन किया है।

18 फरवरी को होगा श्रमिक सम्मेलन का आयोजन

रायपुर। श्रम विभाग कोरबा द्वारा जिले के श्रमिकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से 18 फरवरी (बुधवार) को प्रातः 11 बजे से राजीव गांधी ऑडिटोरियम, टी.पी. नगर कोरबा में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित श्रमिक हितैषी योजनाओं की जानकारी एवं सुविधाएँ अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुँचाने हेतु आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखन लाल देवांगन, मंत्री - वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर एवं श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद, कोरबा लोकसभा, श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत द्वारा की जाएगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर, नगर पालिक निगम कोरबा, श्रीमती संजू देवी राजपूत, अध्यक्ष, जिला पंचायत कोरबा, डॉ. पवन कुमार सिंह तथा सभापति, नगर पालिक निगम कोरबा, श्री नूतन सिंह ठाकुर सम्मिलित होंगे। श्रमिकों की सुविधा हेतु कार्यक्रम स्थल पर पंजीयन एवं नवीनीकरण काउंटर सहित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिससे श्रमिक भाई,बहन स्थल पर ही अपनी आवश्यक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ विकास और विश्वास को समान महत्व दिया

ग्राउंड से ग्रोथ तक- छत्तीसगढ़ में साय सरकार का सुशासन मॉडल

रायपुर। छत्तीसगढ़ आज ग्रामीण विकास के उस मुकाम पर खड़ा है, जहाँ नीतियाँ केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि ज़मीन पर ठोस बदलाव का माध्यम बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन को केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि कार्यशैली के रूप में अपनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महात्मा गांधी नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास का एक उभरता मॉडल बना दिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बीते दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में 8 लाख से अधिक पक्के आवासों का निर्माण पूर्ण होना, देश में सर्वाधिक है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री श्री साय का मानना है कि आवास केवल छत नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और आत्मसम्मान का आधार है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने आवास योजना को आजीविका से जोड़ा है। आवास हितग्राहियों को सेंटरिंग प्लेट एवं अन्य निर्माण की आपूर्ति कर 8 हजार से अधिक महिलाएँ 'लखपति दीदी' बन सकीं।

छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चुनौती रहे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ विकास और विश्वास को समान महत्व दिया है। कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वास योजनाओं के माध्यम से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। आर-सेटी एवं प्रोजेक्ट उन्नति के जरिए आत्मसमर्पित नक्सलियों सहित 5 हजार से अधिक हितग्राहियों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं, 3416 आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई है। पीएम-जनमन आवास योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 33 हजार से अधिक आवासों की स्वीकृति इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। साय सरकार ने योजनाओं की निगरानी में आम नागरिक को सहभागी बनाकर पारदर्शिता को नई परिभाषा दी है। टोल-फ्री हेल्पलाइन, पंचायत स्तर पर क्यूआर कोड और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी व्यक्ति विकास कार्यों की जानकारी सीधे प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मनरेगा, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और पीएम सूर्यघर जैसी योजनाओं से अभिसरण के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे समग्र लाभ सुनिश्चित हो रहा है।

अध्यक्ष सरदार हरजिंदर सिंह धामी का छत्तीसगढ़ सिख समाज ने किया सम्मान, सौंपा ज्ञापन

रायपुर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी के छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज द्वारा उनका हार्दिक स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा ने अपने पदाधिकारी सहित उन्हें शॉल सिरोपाव भेंट कर सम्मानित किया।

छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज की ओर से प्रदेश में निवासरत सिक्ख समाज से संबंधित विभिन्न आवश्यक विषयों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें समाज के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, छात्रावास, समाज के अपने अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधा एवं समाज की मूलभूत व्यवस्थाओं से जुड़े सुझाव शामिल थे। ज्ञापन लेने के बाद सरदार हरजिंदर सिंह धामी ने छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा को शॉल भेंट कर इसी तरह समाज हित में निरंतर सेवा करते रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज की एकता, सहयोग और सेवा भावना की सराहना करते हुए आश्वस्त किया कि प्रस्तुत सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज के नरेंद्र सिंह हरगोत्रा, स्वर्ण सिंह चावला, कुलवंत सिंह खालसा, मनजीत सिंह भाटिया, जागीर सिंह बावा, जसप्रीत सिंह चावला, पुष्पेंद्र सिंह चड्ढा, देवेंद्र सिंह चावला सहित अनेक पदाधिकारी एवं गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने गुरमत परंपरा अनुसार एकजुट होकर समाज की उन्नति के संकल्प को दोहराया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.